राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत–गुजरात,संस्करण शुक्रवार04दिसंबर2020 वर्ष–3, अंक–305पृष्ठ–08, मुल्य–01रुपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बिहार में गंगा नदी पर 15वां पुल बनने का रास्ता साफ, इन तीन राज्यों की दूरी घटेगी

पटना। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बेगूसराय के मटिहानी से शाम्हो के बीच बनने वाले पुल की संभाव्यता रिपोर्ट को सही पाया है। इसी साल जून में ही पुल बनने की संभावना तलाशने (फिजिबिलिटि रिपोर्ट) का काम शुरू हुआ था जो अब पूरा हो गया है। एनएचएआई ने पाया है कि इस इलाके में पुल की जरूरत है। यह पुल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15वां पुल होगा। अब एनएचएआई ने एक एजेंसी को इस पुल के लिए डीपीआर बनाने का जिम्मा दिया है। डीपीआर बनने के बाद इसके निर्माण के लिए वित्तीय व अन्य प्रक्रिया की मंजूरी दी जाएगी। बेगूसराय के मटिहानी-शाम्हो के बीच पुल के बनने से बेगूसराय से लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर आना-जाना और आसान हो जाएगा। दरअसल, पुल बनाने की मांग को लेकर भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इसके बाद ही केंद्र के निर्देश पर एनएचएआई ने पुल बनाने की संभावना तलाशने का काम शुरू किया था। जिस रास्ते पर पुल बनाया जाना है, वह रास्ता पहले शाम्हो-नेपाल मार्ग के नाम से जाना जाता था। अब यह मटिहानी-शाम्हो के नाम से जाना जाता है। किसानों की ओर से पहले से ही जमीन दिए जाने के कारण प्रस्तावित पुल के कई स्थानों पर 80 फीट तक चौड़ी कच्ची-पक्की सड़क है। गंगा नदी पर बनने वाला यह पुल एनएच 31 और एनएच 80 को जोड़ेगा। पुल के बन जाने से बिहार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा आने-जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। तीनों राज्यों की दूरी 76 किलोमीटर कम हो जाएगी। इलाके के दो लाख किसानों को अपना उत्पाद बेचने में भी सुविधा होगी। पुल के बन जाने पर मुंगेर और भागलपुर से आपदा टीम 40 मिनट के भीतर आ जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

चार धाम सड़क परियोजना पर बंटे हुए हैं सरकार के अपने मंत्रालय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मे बताया कि चार धाम सड़क परियोजना को लेकर सरकार के खुद के मंत्रालय बंटे हुए हैं। अदालत ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने पर एक ही पेज पर नहीं दिखाई देते हैं। दोनों की बातों में अंतर दिखाई देता है। भारत-चीन वीं लद्दाख में तनाव के हालात को देखते हुए मंत्रालय ने सड़कों के लिए निर्धारित 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर सात मीटर करने की मांग की है। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ÷ऐसा लगता है कि आपके अपने मंत्रालय एक-दूसरे के साथ नहीं हैं और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं पीठ रक्षा मंत्रालय के हलफनामें का उल्लेख कर रही थी। हलफनामे में शिकायत की गई कि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सड़कों की चौड़ाई पर 2012 और 2018 में

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा।

इन सर्कुलर्स ने पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों में सड़कों के चौड़ीकरण को प्रतिबंधित कर दिया, जो हर दिन चलने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर थे, MoD ने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों और तोपखाने की आवाजाही से संबंधित पहलुओं की अनदेखी की गई थी। रक्षा मंत्रालय के एफिडेविट में कहा गया कि न ही 5 अक्टूबर 2012 का सर्कुलर, न ही 23 मार्च और न ही 2018 की सर्कुलर तारीखों में देश की सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान रखा गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि MoRTH के सर्कुलर देश की सीमाओं के लिए सैनिकों, सेनाओं, तोपखानों और टैंकों की आवाजाही के लिए जरूरी सड़कों का सौदा नहीं करते हैं, इसलिए देश की आक्रामकता के खिलाफ बचाव किया जा सकता है और इसलिए उस विशेष परिस्थिति को कवर नहीं किया जा सकता है जो राज्य आज सामना कर रहा है।

अपने हलफनामे में, MoD ने 2018 में MoRTH परिपत्र के संदर्भ में, पूरे प्रोजेक्ट के लिए सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर तय करने के लिए 8 सितंबर के आदेश को संशोधित करने का अनुरोध किया। MoD ने अनुरोध किया कि ऋषिकेश से माणा तक, ऋषिकेश से गंगोत्री तक और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्र की सुरक्षा के हित में 7 मीटर की चौड़ाई के साथ 2 लेन विन्यास में विकसित किया जा सकता है।

एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली। एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह निधन हो गया. सुबह करीब 5 बजकर 38 मिनट पर महाशय धर्मपाल गुलाटी ने अंतिम सांस ली. महाशय धर्मपाल 98 साल के थे. पिछले दिनों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन वह कोरोना से ठीक हो गए थे. बताया जाता है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी को गुरुवार सुबह हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया. पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

पिछले दिनों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन वह कोरोना से ठीक हो गए थे. बताया जाता है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी को गुरुवार सुबह हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया. पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

सालों से महाशय धर्मपाल गुलाटी एमडीएच मसालों के विज्ञापन में आ रहे थे. धर्मपाल गुलाटी के पिता ने पाकिस्तान के सियालकोट में साल 1922 में एक छोटी सी दुकान से इस सफर की शुरुआत की थी. देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया. ऐसी भी खबरें आती रहीं हैं कि दिल्ली आने के बाद धर्मपाल गुलाटी ने एक तांगा खरीदा था, जिससे वह सवारी को लाते ले जाते थे.

हालांकि इस काम में न तो धर्मपाल गुलाटी का मन लगता था और न ही उन्हें इतनी आमदनी होती थी. इसके बाद साल 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान ली, जिसका नाम 'महाशयां दी हट्टी' रखा. तब से ये दुकान MDH के नाम से जानी जाने लगी. धीरे धीरे धर्मपाल गुलाटी के मसाले लोगों को इतने पसंद आने लगे कि इनका निर्यात दुनियाभर में होने लगा. साल 2017 में उन्हें इंडिया में किसी भी स्वस्थ्त कंपनी का सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला CEO भी घोषित किया गया था.

बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है अलकायदा

यू-ट्यूब के जरिए ऑनलाइन चरमपंथ बढ़ाने की भी कोशिश

नई दिल्ली। अलकायदा अपने यू-ट्यूब चैनलों और ऑनलाइन सामग्री के जरिए बांग्लादेश में जबरदस्त पैठ बढ़ा रहा है। इस ऑनलाइन चहलकदमी से भारतीय एजेंसिया चौकन्ना हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कट्टरता की मुहिम का असर भारत के भी विभिन्न इलाकों पर पड़ रहा है। लेकिन भारतीय एजेंसियां सतत निगरानी कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की फेसबुक पोस्ट पर करीब 250 फीसदी इंटरैक्शन बढ़ी है। वर्ष 2019 में अगर 99 युवा हिंसक चरमपंथी पोस्ट पर इंटरैक्ट करते थे तो 2020 में यह बढ़कर 347 हो गया। एक्यूआईएस के समर्थन में इस्लामिक ब्लॉगर्स की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2020 की शुरुआत में बांग्लादेश में इंटरनेट का इस्तेमाल 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया।एजेंसियो का कहना है कि बढ़ती कनेक्टिविटी का फायदा चरमपंथियों ने भी उठाया है। एक्यूआईएस से जुड़े कई यू-ट्यूब चैनलों ने कोविड सामग्री के बहाने कट्टरपंथी सामग्री परोसी और उनके

सब्सक्रिप्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सूत्रों ने कहा ऑनलाइन कट्टरपंथ की चुनौती पर भारत और बांग्लादेश की एजेंसिया एक-दूसरे को सहयोग कर रही हैं। निगरानी से लेकर ऑनलाइन कंटेंट विश्लेषण का काम चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश के अलावा भारत मे भी पिछले दिनों जो युवा कट्टरपंथी गतिविधियों की वजह से पकड़े गए हैं वे ऑनलाइन चरमपंथी चैनलों और पोस्ट से प्रेरणा लेते थे।

सामान्य रेल यात्री सेवा जल्द बहाल होने के आसार नहीं, कोरोना के कारण चलती रहेंगी स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों के चलते सामान्य रेल यात्री सेवा के जल्द बहाल होने के आसान नहीं है। रेलवे फिलहाल स्पेशल ट्रेनों के जरिए ही सीमित संख्या में ट्रेनें चला रहा है। कोरोना काल में यात्रियों की संख्या भी घटी है और बिहार बंगाल जाने वाले रूट को छोड़कर अन्य रूट पर भीड़ काफी कम है।

कोरोना काल में रेलवे के राजस्व का अधिकांश हिस्सा माल भाड़े के जरिए ही आ रहा है। यात्री सेवाओं से मिलने वाला राजस्व बेहद कम है। रेलवे की लगभग दस फीसदी ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है। हालांकि रेलवे के खर्चे उतने कम नहीं हुए हैं। कर्मचारियों के वेतन के साथ ट्रेनों, इंजनों अन्य रखरखाव पर खर्च किया ही जा रहा है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ विनोद कुमार यादव ने साफ किया है कि कोविड 19 के विभिन्न प्रोटोकॉल का रेलवे पूरी तरह पालन कर रही है और वह नियमित यात्री रेल सेवा तभी शुरू करेगा जब गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति मिल जाती है। विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए भी वह राज्यों की मंजूरी पर

निर्भर है, क्योंकि राज्यों को हर स्टेशन पर कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। इसके चलते कई स्टेशनों पर वह सभी ट्रेनों के स्टॉप भी नहीं करवा रहे है।

अगले साल रेलवे को ज्यादा बजट की जरूरत होगी

ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष में नियमित यात्री सेवा बहाल होने के आसार बेहद कम है। इसके चलते अगले वित्त वर्ष में रेलवे पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार अन्य विभागों के साथ रेलवे में भी अगले साल के बजट की तैयारी हो रही है। रेलवे को इस साल राजस्व में आई कमी के चलते अगले साल ज्यादा बजट अनुदान की जरूरत होगी, ताकि वह कोरोना काल के बाद अपनी यात्री सेवाओं को सुचारू ढंग से जारी रख सके।

माल भाड़े से सीमित भरपाई

हालांकि माल भाड़े के जरिए रेलवे ने कुछ हद तक राजस्व घाटे को कम जरूर किया है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे के नई रेल लाइनों, स्टेशनों के निर्माण के ढांचागत भारी भरकम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिससे रेलवे को अभी काफी बजट की जरूरत है। हालांकि उसने अपने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट पीपीपी मोड में शुरू की है ताकि निवेश की समस्या ना आ सके।

बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होगा कोरोना का टीका, तैयारी में जुटा विभाग

पटना। बिहार में कोरोना वैक्सीन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। जिले से वैक्सीन एकत्र कर टीकाकरण कमियों द्वारा कोल्ड चेन को मेनटेंन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने उसके वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कोल्ड चेन व्यवस्थित करने के लिए बन रही टीम-स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि कोल्ड चेन को व्यवस्थित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह टीम सामान्य टीकाकरण की टीम से अलग होगी जो मुख्य रूप से कोरोना वैक्सीन को व्यवस्थित करेगी। कहा कि प्रखंड स्तर तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना से बचाव हो सके। टीकाकरण को लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी।

कोल्डचेन के लिए फ्रीजर की व्यवस्था होगी-स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीन को चिकित्सा सेवा की सबसे निचली इकाई तक पहुंचाने के लिए फ्रीजर की व्यवस्था करनी होगी, ताकि वैक्सीन को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए दिशा-निर्देश केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक डीप-फ्रीजर की व्यवस्था होगी। टीकाकरण में लगने वाली टीम को भी टीकाकरण को लेकर आइस बॉक्स इत्यादि उपलब्ध कराने होंगे।

उत्तर प्रदेश की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को 3 माह में मंजूरी, छोटे शहरों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले तीन माह में उत्तर प्रदेश में दो दर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने जा रही है। सात हजार करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं में 680 किलोमीटर दो लेन और चार लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाया जाएगा। इसमें पांच रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) व एक फ्लाईओवर शामिल हैं। अधिकांश परियोजनाएं मझोले शहरों व कस्बों को जोड़ने वाली हैं। इससे स्थानीय निवासियों को तेज व सुगम यातायात मिल सकेगा।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष (मार्च 2021) तक दो दर्जन

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं पर 7205 करोड रुपये लागत होने का अनुमान है। सभी परियोजनाओं को अगले दो से ढ़ाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं में दो लेन पेव शोल्डर प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा-शृंगवेरमपुर (54 किमी) का खंड भी शामिल है। इस पर 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यह खंड रामवन गमन पथ परियोजना का हिस्सा है। इसी कड़ी में दो लेन पेश शोल्डर रामपुर-सिकरीगंज (31 किमी) राष्ट्रीय राजमार्ग पर 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह खंड राम जानकारी मार्ग परियोजना का हिस्सा है। दोनों परियोजनाओं को दिसंबर- 2020 में मंजूरी दे दी जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुशंसा पर रामवन गमन पथ के एलाइनमेंट में परिवर्तन किया गया है। इसलिए भूमि अधिग्रहण के लिए मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त 452 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार- केरल के पत्रकार की गिरफ्तारी में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 अक्टूबर को हाथरस के पास से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ उसके कथित संबंधों की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने बताया कि जिस अखबार में काम करने का दावा पत्रकार ने किया है वो तो तीन साल पहले बंद हो चुका है। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने कप्पन की ओर से दायर हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की है, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा, ÷एक एसोसिएशन अपनी ओर से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे लड़ सकता है ... वह (कप्पन) थेजस नामक एक पेपर के पत्रकार होने का दावा करता है जो तीन साल पहले बंद हो गया था। उसके खिलाफ अब तक की गई जांच चौंकाने वाली है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार सिद्दीकी कप्पन हाथरस के कथित गैंगरेप और मर्डर पर रिपोर्टिंग करने के लिए शहर जा रहे थे, उसी दौरान 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि उनके साथ तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। 7 अक्टूबर को पुलिस ने सभी के खिलाफ राजद्रोह और क्के सेक्शन 17 के तहत मामला दर्ज किया था. इस सेक्शन के तहत आतंकी गतिविधि के लिए फंड जुटाने के मामले में सजा का प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स KUWJ के लिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा और ऐसी कोई भी मिसाल लाने के लिए कहा, जहां एक एसोसिएशन या यूनियन ने एक आपराधिक मामले में जेल में बंद व्यक्ति की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की हो। सुप्रीम कोर्ट कप्पन की गिरफ्तारी देने वाली केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सिब्बल ने अदालत से कहा कि वो मामले पर इसी अदालत में सुनवाई करेंगे और वे कप्पन की पत्नी को अपनी याचिका में एक पार्टी के रूप में जोड़ने के लिए सहमत हुए। पीठ ने जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम को भी शामिल करते हुए कहा, ÷भले ही आप पत्नी (कप्पन की पत्नी) को निकाल दें, फिर भी हम आपसे पूछेंगे कि आपको उच्च न्यायालय में क्यों नहीं जाना चाहिए।

सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सीधे हस्तक्षेप करने का उदाहरण दिया और इसे न्यायालय की एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध था।

लेकिन पीठ ने यह कहते हुए उसे अलग कर दिया कि ÷प्रत्येक मामले के तथ्य अलग होते हैं।÷ पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए तैनात किया जिससे राज्य को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की प्रतिक्रिया और पत्रकार संघ कोप्पन की पत्नी को कार्यवाही में शामिल होने का समय मिल सके।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

वैक्सीन से खुशी

वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। कोरोना वैक्सीन फाइजर/ बायोएनटेक को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है और वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले सप्ताह से यह वैक्सीन ब्रिटेन में उपलब्ध होने लगेगी। वैक्सीन तब आई है, जब दुनिया भर में 6.4 करोड़ से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इस वैक्सीन को 95 प्रतिशत कारगर बताया जा रहा है और इससे कोरोना संक्रमण रोकने का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। पहले दौर में उन लोगों को वैक्सीन का लाभ दिया जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं और ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन की चार करोड़ खुराक तैयार करने का आदेश दे रखा है और दो करोड़ लोगों को खुराक दी जा सकेगी। एक व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए दो खुराक की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन के बाद अब निगाहें अमेरिका की ओर हैं, जहां अगले सप्ताह वैक्सीन पर फैसला होना है। संभावना है, वहां एक ही साथ एकाधिक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने वाली है। हमारी दुनिया के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, जब किसी बीमारी के विरुद्ध वैक्सीन बनाने में बमुश्किल दस महीने का समय लगा है। इसके लिए विज्ञान और चिकित्सक बिरादरी के प्रति जितना आभार जताया जाए, कम होगा। हालांकि, इस संकटमोचक बिरादरी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन के असर को लगातार परखना होगा, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाया जा सके। जब उपचार में तीन-चार प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग होगा, तब लोग जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर है और इसके अलावा लोगों को वैक्सीन के किफायती होने की उम्मीद भी रहेगी। वैक्सीन के आने की सुखद आहट के असर जीवन के विविध क्षेत्रों में दिखने लगे हैं। दिसंबर का महीना है और भारत की शान आईआईटी में प्लेसमेंट का पहला दौर भी शुरू हो गया है, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। एक अमेरिकी कंपनी ने एक छात्र को रिकॉर्ड 1.54 करोड़ रुपये का पैकेज ऑफर किया है। प्लेसमेंट के पहले दिन भारतीय कंपनियों ने भी 80 लाख रुपये सालाना का पैकेज प्रस्तावित किया है। पहले दिन प्रस्तावित नौकरियों के आधार पर अगर देखें, तो पिछले वर्ष की तुलना में न सिर्फ 20 प्रतिशत नौकरियां ज्यादा हैं, बल्कि पैसे भी 20 प्रतिशत ज्यादा प्रस्तावित किए जा रहे हैं। पिछले साल औसतन 60 लाख तक के पैकेज प्रस्तावित हुए थे और इस बार प्रस्ताव 80 लाख रुपये सालाना तक पहुंच गए हैं। कोरोना के समय में इतने बड़े पैमाने पर नौकरी व वेतन-भत्ते का प्रस्ताव उत्साहवर्द्धक है। आशंका थी कि इस बार नौकरियों व अच्छे पैकेज का टोटा पड़ेगा, पर अब जब वैक्सीन की आहट सुनाई पड़ने लगी है, तब कंपनियों का विश्वास भी बढ़ा है। वैक्सीन के आने से पूरे आर्थिक जगत में सकारात्मक माहौल बन रहा है। वैसे यह गौर करने की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोरोना के समय भी बढ़त और मांग की स्थिति बनी रही है। बेशक, शुरुआती आंकड़े उत्साहजनक हैं। प्लेसमेंट के जब अंतिम आंकड़े आएंगे, तब हमें समझने में आसानी होगी कि सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल इत्यादि में नौकरी व पैकेज की क्या स्थिति है। सभी क्षेत्रों में नौकरी व पैकेज बढ़े, तो ही दुनिया के लिए असली खुशखबरी होगी।

आज के ट्वीट

दान

फ्रांस के राजदूत महाकाल की शरण में आए,और दर्शन के बाद उन्होंने घोषणा भी की कि फ्रांस की सरकार 'महाकाल मंदिर के विकास हेत' 80 करोड़ रुपए दान करेगी।

-- पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ

यूपी में फिल्म सिटी

– सियाराम पांडेय 'शांत'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय फिल्म सिटी बनाने की घोषणा क्या की, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उसी दिन से प्रलाप की मुद्रा में आ गए। अब जब योगी आदित्यनाथ मुंबई में हैं और वहां के एक होटल में उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों से बात की है और उन्हें अपनी परियोजना से अवगत कराया है, तब उद्धव ठाकरे के राजनीतिक प्रलाप में और तेजी आ गई है। मराठी मानुष की बात करने वाली शिवसेना और मनसे को लग रहा है कि फिल्म सिटी यूपी गई तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचेगा। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई पहुंचते मनसे ने वहां के चौक-चौराहों पर मराठी भाषा में पोस्टर टंगवा दिए। पोस्टर में लिखा है कि 'दादासाहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म सिटी को यूपी ले जाने के मुंगेरी लाल के सपने हैं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कहां महाराष्ट्र का वैभव और कहां यूपी की दरिद्रता। नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाने आया है ठग। भले ही प्रत्यक्ष तौर पर योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं है लेकिन उनके लिए ठग जैसा संबोधन न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायोचित। जब शिवसेना और मनसे को पता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच कोई समानता नहीं है तो फिर उसके नेता बौखलाए से क्यों हैं? इस बात का जवाब तो खैर उन्हें ही देना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि भाजपा बॉलिवुड का एक टुकड़ा इस उत्तरी राज्य में ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत को लगता है कि मुम्बई की 'फिल्म सिटी' को कहीं और स्थापित करना आसान नहीं है। उसे लखनऊ या पटना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मुंबई का शानदार फिल्मी इतिहास रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि मुंबई को फिल्मिस्तान बनाने में अकेले मुंबईकरों का हाथ नहीं है। देशभर के कलाकारों की भावनाएं, संवेदनाएं और श्रम उससे जुड़े हैं। बालीवुड को बॉलीवुड बनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की भी अहम भूमिका रही है। फिर कला किसी क्षेत्र विशेष का एकाधिकार नहीं। मराठी मानुष के नाम पर महाराष्ट्र में कब-कब क्या-क्या हुआ है, परप्रांतियों के साथ कितनी ज्यादतियां हुई, यह किसी से छिपा नहीं है। अपने जिस स्वनामधन्य पिता के कसीदे उद्धव ठाकरे गढ़ रहे हैं, उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ अभियान छेड़ा। उनकी नजर में राष्ट्रीयता नहीं, क्षेत्रीयता अहम थी। यूपी-बिहार के लोगों के साथ भी शिवसेना और मनसे का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि देश को बॉलीवुड से भी अच्छी फिल्म सिटी की दरकार है और इस निमित्त वे विश्वस्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। फिर कलाकार तो वहीं जाएगा जहां सम्मान, दाम और सुविधाएं पाएगा। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, मनसे और राकांपा नेताओं के विरोध को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सटीक और पते की बात कही है कि वह किसी राज्य से कुछ भी कहीं नहीं ले जा रहे हैं। यूपी में फिल्म सिटी वहां की मांग और जरूरतों के हिसाब से बन रही है। मुंबई की फिल्म सिटी अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करेगी। हम उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं इसीलिए फिल्म जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुंबई में हैं तो इसलिए कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। वहां ज्यादातर पूंजीपतियों के व्यापार और मुख्यालय हैं। वे उद्योगपतियों से भी बात कर रहे हैं और फिल्मी कलाकारों से भी। केवल बात करने से कोई किसी के पीछे नहीं चल देता। उसे सहमत करना पड़ता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अगर यह लगता है कि मुंबई के उद्योगपति यूपी जा सकते हैं तो उन्हें सहमत करने और यूपी जाने से रोकने का मार्ग स्वत- अपना सकते हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के होटल पर प्रदर्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कोरोना काल में जब महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर काम के अभाव में पैदल अपने घरों के लिए निकल पड़े थे तब भी योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि वे अपने राज्य के मजदूरों को अन्य राज्यों में नहीं जाने देंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश में ही काम देंगे और बहुत हद तक उन्होंने मजदूरों से किया गया वादा निभाया भी। योगी आदित्यनाथ की इच्छाशक्ति ही है कि उनके मुंबई जाने भर से वहां के मुख्यमंत्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी को लेकर मुंबई के उद्यमियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से बातचीत की है। यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव, सुझाव और सहयोग मांगे हैं। जिस तरह यूपी सीएम उद्यमियों से बात कर रहे थे, उसी दौरान होटल के बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूपी सरकार के एक मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि अंडरवर्ल्ड के जरिए धमकी दी जा रही है कि यूपी में फिल्म सिटी न बने। दरअसल यह सब चल क्या रहा है। अगर दक्षिण के राज्यों में फिल्म सिटी बन सकती है तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। फिर योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यूपी फिल्म सिटी में केवल हिदी फिल्में ही नहीं बनेंगी। वहां दक्षिण की फिल्में भी बनेंगी और अंग्रेजी की फिल्में भी बनेंगी। फिर संजय राउत का यह कहना कि योगी दक्षिण के राज्यों के कलाकारों से ही क्यों नहीं मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कलाकारों से नहीं मिल रहे हैं। वे मुंबई ही क्यों आए हैं? इस तरह के बिना सिर-पैर के सवाल परेशान करने वाले हैं। हर प्रांत के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की बेहतरी का प्रयास करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का ट्वीट है कि जब भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब कई उद्योग एवं कार्यालय गुजरात स्थानांतरित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर अब बॉलीवुड का एक टुकड़ा ले जाने की पटकथा तैयार कर रही है। भाजपा के शासनकाल में जो कुछ हुआ, हम फिर वह नहीं होने देंगे।' इसे दिमागी दिवालियापन नहीं तो और क्या कहा जाएगा? सवाल यह उठता है कि उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र का हक छीनने आए हैं। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में एक फिल्म सिटी स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना सितंबर में सामने रखी थी और फिल्म बिरादरी को फिल्म निर्माण के वास्ते उत्तर प्रदेश आने की पेशकश की थी। तभी से इस प्रकरण पर शिवसेना और भाजपा में तनातनी है।नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से उद्धव ठाकरे नाराज हैं और कह रहे हैं कि वे ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है। उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। गत 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नोएडा क्षेत्र में एक भव्य और विशाल फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी तो एकबारगी लगा था कि अभी यह एक घोषणा ही है, जो न जाने कब शुरू और कब पूरी होगी लेकिन योगी ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, वह बताती है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। फिल्म सिटी की इस योजना को पंख तब लगे जब 22 सितंबर को ही मुख्यमंत्री योगी ने इसकी मीटिंग के लिए कुछ फिल्म वालों को लखनऊ में लंच पर बुला लिया। इससे यह संदेश गया कि योगी फिल्म सिटी की योजना को लंबा न खींचकर जल्द से जल्द पूरा करने का मन बना चुके हैं। अब उद्धव और उनकी टीम सोचे कि उसे अपनी जरूरतों की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कुछ करना है।

(लेखक हिन्दुस्तान समाचार से संबद्ध हैं।)

ज्ञान गंगा

दान

श्रीराम शर्मा आचार्य

दान का अर्थ है देवत्व के अनुरूप देते रहने की वृत्ति को जिंदा रखना। शास्त्र कहता है-सौ हाथों से कमाओ, हजार हाथों से बांटो। दुनिया में सम्मान उनके लिए ही सुरक्षित है जो देते रहते हैं, पर बदले में कम पाने पर भी अपना काम चला लेते हैं। दो और पाओ, बोओ और काटो, बांटो और झोली भर लो का सिद्धांत एक शात सत्य के रूप में सदा से कार्य करता आया है। आज का समय बड़ी अभूतपूर्व घड़ियों में आया है। यह एक असाधारण समय है। ऐसे में धन-साधन के बाद सबसे महत्वपूर्ण जिसे माना गया है, वह है-समयदान। यह सभी के लिए सुलभ है। यदि समयदान के साथ श्रद्धा का पुट और लग जाए तो लोक मंगल के अनेक कार्य संभव हैं। महान मनीषियों की साधना समय की तपःशिला पर बैठकर ही संपन्न हुई है। लोकसेवियों ने समयदान के सहारे अनेक असंभव कार्य कर दिखाए हैं परन्तु यह कार्य तभी बन पड़ता है, जब अंतराल की गहराई से आदशरे के राजमार्ग पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस निरंतर उठती है। आज आस्था पर संकट रूपी दुर्भिक्ष जब प्रेत-पिशाच की तरह चढ़ा हुआ है, समयदान को युगधर्म मानकर तत्काल उसमें जुटना होगा। श्रेष्ठ कार्य यदि सामने हो तो उसे तुरंत करना चाहिए, यह उक्ति चरितार्थ करते हुए युग संधि महापुरचरण की वेला में सभी को बढ़-चढ़कर समयदान करना चाहिए। दान-पुण्य शब्द एक साथ मिलकर बोले जाते हैं और इनके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। अध्यात्म की भाषा में इनकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में कही जाती है और बोलचाल की भाषा में इन्हें प्रगति, सफलता, वरिष्ठता और प्रदाता तक बताया जाता है। दान अर्थात देना, यही पुण्य है। लेना अर्थात अधिकारों का अपहरण, यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र में अवगति-दुर्गति स्तर की होती है। नरक इसी का आलंकारिक प्रतिपादन है। दोनों में से अपनी गतिविधियां किस पक्ष के साथ विनियोजित करना है, यह मनुष्य की अपनी इच्छाओं की बात है। परिस्थितियां कई बार इस चयन के विपरीत दबाव भी डालती देखी गई हैं पर अंतत- होता वही है, जिस पर इच्छा-शक्ति संकल्प बनकर केंद्रीभूत होती है।

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक समस्या सुलझाने में आप सफल होंगे। रक्तचाप या हृदय रोगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। टकराव की स्थिति आपके हित में न होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं।

वृषभ पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

मिथुन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कर्क राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खानपान में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे

सिंह पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जनों से तनाव मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन लाभ होगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। वाणी की सौम्यता आवश्यक है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

तुला पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप होगा। धन हानि की संभावना है।

वृश्चिक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। विरोधियों का पराभव होगा।

धनु आर्थिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। जारी प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा।

मकर जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

कुम्भ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पारिवारिक जनों से तनाव मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।

मीन व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

चुनावी मुद्दा बने स्वास्थ्य सुविधाएं

सत्य मोहंती

स्वास्थ्य देखभाल नीति निर्धारण में दिखावे की शोशेबाजी की जगह ठोस काम करने की जरूरत होती है! अक्सर हमें चमकदार और प्रभावित करने वाली उद्घोषणाएं देखने को मिलती हैं। कोविड-19 महामारी नींद से जगाने का अवसर बनकर आई है। इससे भी बदतर यह है कि राजनेताओं की अन्य तरजीहों के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में जो स्थिति और राहें चुनी गई हैं, वे सर्वोत्कृष्ट नहीं हैं। अब यह बात शक से परे है कि जब तक सुधार करने को राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होगी, तब तक महसूस करने लायक बदलाव होना संभव नहीं है। वह स्थिति तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जहां प्रतिद्वंद्विताहीन व्यवस्था बना दी जाए। वह भी तब जब समाज के 80 फीसदी हिस्से के लिए अपनी जेब से ढंग की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का वहन मुश्किल हो या फिर निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुविधाएं पहुंच से बाहर हों (नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार)। नतीजतन, निस्संदेह सरकार सही जगह पैसा लगाने में चूक गई है। पड़ोसी बांग्लादेश ने स्वास्थ्य सेवा में पैसा लगाया। उन्होंने यह करते वक्त चकाचौंध करने वाली सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने पर ध्यान न देकर व्यावहारिक व्यवस्था अपनाकर सही जगह निवेश किया। आज उनका सामाजिक स्वास्थ्य सूचकांक देखने योग्य है लेकिन अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाने और सुधार करने के लिए हम कौन सा बटन दबाएं? किन सुधारों की जरूरत है, इसका इल्म सबको है। किंतु चीज़ों को सही करने की बजाय 'चलता है' वाला टालमटोल वाला रवैया अपनाया जाता है। मौजूदा मजबूत राजनीतिक नेतृत्व से काफी उम्मीदें जगी हैं, लेकिन क्या वह इस खामी को दुरुस्त कर पाएगा? यदि एक बार यह तय कर ले तो क्रियान्वयन सही राह और सही जगह पर होगा। दरअसल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की एवज पर बीमारी के दूसरे या तीसरे चरण में जरूरत पड़ने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बीमा योजना का प्रावधान करना आगे बढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। हो सकता है यह योजना कॉर्पोरेट अस्पतालों को मदद देने के लिए अच्छी हो लेकिन आमजन की स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा नहीं करती। ठीक इसी वक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सार्वजनिक अस्पतालों की सहायता करने में नेतृत्व की स्वैच्छिक अनिच्छा साफ दिखाई देती है। बहुसंख्यक लोगों के लिए इनका खर्च उठाना बस में नहीं है, इस तरह यह सुविधाएं उनकी पहुंच से दूर बन जाती हैं। धन और कर्मियों की कमी झेलने वाले मौजूदा सरकारी अस्पतालों की समस्याओं को हल करने की चुनौती आसानी से हाशिए पर सरका दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20 फीसदी डॉक्टर कम हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में 30 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी है। अगर बजट काफी बढ़ा भी दिया जाए तो भी यह फिजूल के नए विचारों को अमल में लाने पर बेकार कर दिया जाएगा। यथास्थिति बनाए रखने हेतु जानबूझकर ध्यान वहां केंद्रित रखा जाता है जहां बुद्धि लगाने की जहमत न उठानी पड़े। जब हमारी 80 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सकों के पास इलाज हेतु जाती है तो राजनीति का अर्थशास्त्र नर्सिंग स्नातकों को ग्रामीण इलाकों में नर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी बनने की इजाजत क्यों नहीं देता, जबकि ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र को काफी लाभ होगा। इसकी बजाय ज्यादा जोर डॉक्टर बनाने पर दिया जा रहा है, वह भी यह बात भली भांति जानते हुए कि वे ग्रामीण इलाके में काम करना पसंद नहीं करेंगे। हैरानी की बात है, वह देश जहां 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 50 करोड़ ऐसे हैं जो कभी भी फिसलकर इस श्रेणी में आने की जद में हैं, उनके लिए बीमा योजना बनाकर निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों के भरोसे करना अनाड़ीपन ही तो है। यह अपरिहार्य बेमेल स्थिति और कहीं इतनी ज्यादा साफ देखने को नहीं मिली, जितनी कोविड-19 के दौरान हुई है, जब निजी अस्पतालों ने या तो कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया या फिर जमकर पैसा बनाया है। क्या राजनेता-नौकरशाही पर टिके तंत्र को अपनी दिशा बदलने को मजबूर किया जा सकता है? स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन बोर्ड में राजनेताओं को जगह देने का नतीजा यह है कि अपने सीधे हस्तक्षेप से वे सही काम भी बिगाड़ देते हैं। उनका मार्गदर्शन करने को सुविज्ञ परामर्शदाता होने चाहिए। इसकी बजाय हम देख रहे हैं कि निजी निवेशकों को बीच में लाकर पसंदीदा कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने की कुटिल नीति अपनाई जा रही है। हैरानी की बात है कि जिस प्रणाली पर देश का लगभग 80 फीसदी मतदाता आश्रित है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं, इन्हें कोई भी दल असली मुद्दा नहीं बनाता। कुछ प्रक्रियाओं के जरिए राजनीतिक प्रतिष्ठान लाभ-आवंटन बदल देते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों को यथेष्ठ धन से महरूम रखकर कॉर्पोरेट अस्पतालों को फायदा पहुंचवाते हैं। अब उन्होंने ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है, जिसके चलते निजी अस्पतालों को खूब ग्राहक मिल रहे हैं, नतीजतन सार्वजनिक संस्थान खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अनदेखी सहनी पड़ रही है। एक बार यह चुनावी मुद्दा बन गया तो राजनेता इस पर प्रतिक्रिया करने को बाध्य हो जाएंगे। ऐसा होने पर राजनेता वोट के बदले स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने पर बाध्य हो जाएंगे। दोनों पक्ष यानी जनता और राजनीतिज्ञों को साथ मिलकर काम करना होगा और यह प्राप्ति ठोस काम किए बिना संभव नहीं है। उम्मीद करें कि अगली बार जब महामारी झेलनी पड़े तो उस वक्त देश 'अर्धसत्यों' और 'तदर्थ उपायों' के जरिए जूझता दिखाई न दे।

आप इस समाचार के बारे में क्या विचार रखते हैं?

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारतीय खिलौना उद्योग में ज्यादातर खिलौने China और ताइवान के : निशंक

नई दिल्ली। भारत खिलौनों का एक बड़ा बाजार है, करोड़ों रुपये का यह भारतीय खिलौना उद्योग काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत में बेचे जाने वाले ज्यादातर खिलौने **China** और ताइवान से आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने भारतीय शिक्षा संस्थानों के युवाओं को खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु एक टॉयथॉन चैलेंज 2020 शुरू किया। यह आयोजन अमेजॉन इंडिया द्वारा देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के युवा इनोवेटर्स को भारतीय संस्कृति, लोक-कलाओं और मूल्यों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय खिलौना उद्योग के बारे में बात करते हुए डॉ. निशंक ने कहा, भारतीय खिलौना उद्योग करोड़ों का है, और यह काफी हद तक आयात पर निर्भर है, जबकि भारत में बेचे जाने वाले ज्यादातर खिलौने **China** और ताइवान से आते हैं। भारत में खिलौना निर्माण में मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व है। इस सेक्टर में हजारों एमएसएमई काम कर रहे हैं। इससे भारत में खिलौना उत्पादन के क्षेत्र में हमारे अकादमिक ज्ञान एवं उद्योग जगत के बीच गैप का पता चलता है। इस अन्तराल को खत्म करने के लिए ही हम नई शिक्षा नीति सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि खिलौना निर्माण में भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है, और देश भर में अनेक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि भारत के लिए इन श्रेष्ठताओं का लाभ उठाने और एक फलता-फूलता स्वदेशी खिलौना बाजार विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जैसा कि **Prime Minister** ने अपने मन की बात सम्बोधन में भी कहा था कि भारत में कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली और असम में धुबरी तक स्थानीय खिलौनों की एक फलती-फूलती परंपरा रही है। इस संभावना का लाभ उठाना, हमारे यशस्वी **Prime Minister** आत्मनिर्भर भारत के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम बढ़ाना होगा। **Prime Minister** ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय खिलौना बाजार में भारी संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर इस उद्योग में प्रगामी परिवर्तन किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने खिलौना निर्माण के क्षेत्र में इनोवेशन की बात करते हुए कहा कि राष्ट्र की युवा प्रतिभाओं को खिलौना निर्माण के क्षेत्र में इनोवेटिव डिजाइनों और प्रक्रियाओं के साथ आगे आना होगा, जिनके माध्यम से हम बच्चों की कल्पनाशील-गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं और उन्हें भारत की समृद्ध संस्कृति से परिचित करा सकते हैं। डॉ. निशंक ने कहा, शिक्षा, मनोरंजन और सहभागिता पर केंद्रित अमेजॉन का टॉयथॉन चैलेंज हमारे युवाओं द्वारा खिलौना डिजाइन और तकनीक में नवप्रवर्तनों का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने के लिए है, ताकि हमारे इतिहास और संस्कृति पर गर्व की भावना को अधिक बल दिया जा सके। अमेजॉन इंडिया को उनकी संभावनाओं का विस्तार करते देखना और **Prime Minister** नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर आगे आकर ऐसी पहल के साथ नेतृत्व करते देखना काफी सुखद है। टॉयथॉन चैलेंज 2020 में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए डॉ. निशंक ने कहा कि इस तरह के आयोजन से भारत में खिलौना निर्माण उद्योग को बड़ा बल मिलेगा और वैश्विक परिदृश्य में हमारी स्थिति और बेहतर बनेगी।

अमेरिका का चीन को नया झटका, कपास के आयात पर लगाई रोक

वाशिंगटन। अमेरिका ने चीन को नया झटका देते हुए झिंजियांग सरकारी संगठन से कपास के आयात पर रोक लगा दी है। होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने बुधवार को यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। अमेरिका के डिपाटमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने बुधवार को घोषणा की कि सभी अमेरिकी बंदरगाहों पर सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के कर्मचारी, झिंजियांग उत्पादन और निर्माण कोर द्वारा आने वाले कपास और कपास उत्पादों वाले जहाजों को रोक दे।' विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा कार्यालय ने श्रमिकों के उत्पीडन की जानकारी के आधार पर एक्सपीसीसी द्वारा बनाए गए कपास उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

भारत में नवंबर में सर्विस सेक्टर रिकवरी कमजोर : पीएमआई

नई दिल्ली।

भारत के सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) की रिकवरी नवंबर में कमजोर हो गई, जबकि नए कार्य समर्थित व्यापार गतिविधि वृद्धि में तेजी आई है। हालांकि, इस क्षेत्र ने नौ महीनों के दौरान रोजगार में पहली बार वृद्धि भी देखी गई है। इसके अलावा, सकारात्मक धारणा का समग्र स्तर फरवरी की भविष्यवाणियों के बीच उच्चतम स्तर तक चढ़ गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस के लिए एक वैक्सीन मिलने के बाद बाजार की स्थिति सामान्य हो जाएगी। मासिक सर्वेक्षण इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नवंबर में लगातार दूसरे महीने 50 अंक के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर रहा, जो कारोबार में बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि, यह अक्टूबर के 54.1 (इंडेक्स रीडिंग) से घटकर नवंबर में 53.7 (इंडेक्स रीडिंग) रहा, लेकिन ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि कारोबार में सुधार हो रहा है। कोविड-19 के चलते लगाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के बाद मांग तेजी से बढ़ी है। आईएचएस मार्केट रिपोर्ट में कहा गया है, अक्टूबर से विकास में ढील के बावजूद नए कारोबारी प्रवाह में लगातार दूसरे महीने ठोस रूप से वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण प्रतिभागियों के अनुसार, बिक्री में वृद्धि से मांग, विपणन प्रयासों और कोविड-19 नियंत्रणों के ढीले पड़ने की स्थिति में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, आंकडों के आधार पर सुझाव दिया गया है कि कुल नए काम में तेजी घरेलू बाजार द्वारा प्रेरित है और नए निर्यात ऑर्डर के साथ यह नवंबर में फिर से तेजी से घट रही है।

निसान की ऑल-न्यू मैग्नेट एसयूवी की कीमत 4.99 लाख

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल कंपनी निसान इंडिया ने बुधवार को ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट की कीमत की घोषणा की है, जिसकी कीमत 4.99 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो 31 दिसंबर, 2020 तक वैध है। कंपनी ने पूरे देश में इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी हैं। निसान मोटर इंडिया के अध्यक्ष सिनान ओजकोक ने एक बयान में कहा, 'ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट भारतीय और वैश्विक बाजार दोनों के लिए निसान की अगली रणनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की फिलासफी पर आधारित है। ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट 20 से अधिक फर्स्ट-इन-क्लास और बेस्ट-इन-सेगमेंट विशेषताओं के साथ आता है। यह उपभोक्ताओं को एक नया और सुलभ अनुभव देता है।' इसके अलावा, कंपनी ने एक पहला इन-इंडस्ट्री वर्चुअल टेस्ट ड्राइव फीचर भी लॉन्च किया है, इससे ग्राहक अपने निजी डिवाइस पर ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट का अनुभव कहीं भी ले सकते हैं। कंपनी के बयान में कहा गया है, 'यह इंटरैक्टिव ड्राइव अनुभव निसान के ग्राहकों को वर्चुअल सेल्स कंसल्टेंट के साथ 'करिश्माई' एसयूवी को चलाने का एक अनूठा मौका देता है।'

नए अमेरिकी प्रशासन के तहत भारत फिर से ईरान, वेनेजुएला से ले सकता है तेल

नई दिल्ली।

अमेरिका में जो बिडेन प्रशासन के पद्भार संभालने के बाद, भारत एक बार फिर से ईरान और वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति शुरू करने के लिए मामला आगे बढ़ा सकता है। तेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि तेल के एक बड़े आयातक के रूप में, भारत कच्चे तेल के लिए एक विविध बाजार बनाना चाहता है और इसमें, अगर ईरान और वेनेजुएला जैसे पारंपरिक बाजार फिर से शामिल हो जाते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन में बदलाव के साथ संबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बाबत सीमित बातचीत शुरू की जा सकती है कि क्या तेल बाजार के विस्तार के लिए बड़े खरीदारों का रूख किया जा सकता है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते पश्चिमी देशों ने इसपर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। भारत ने मई 2019 से अमेरिकी प्रतिबंधों के फिर से लागू होने से ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी। दूसरी ओर, वेनेजुएला, जनवरी 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है और तेल पर उसकी निर्भरता कम से कम अगले कुछ दशकों तक स्थिर रहने की उम्मीद है। यहां ऊर्जा की खपत 2040 तक सालाना 3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो कि किसी भी अन्य देश के ऊर्जा की तुलना में अधिक है।

रिजर्व बैंक ने HDFC को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका, जानें क्या है वजह

बिजनेस डेस्क।

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उससे अपनी आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी के डेटा सेंटर में पिछले महीने कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिया।

क्या कहा एचडीएफसी बैंक ने

एचडीएफसी ने शेयर बाजार को बताया, 'आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को दो दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी किया है, जो पिछले दो वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है, जिसमें हाल में 21 नवंबर 2020 को प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का बंद होना शामिल हैं।'

कमियों की जांच कर जवाबदेही तय करें- आरबीआई

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि आरबीआई ने आदेश में 'बैंक को सलाह दी है कि वह अपने कार्यक्रम डिजिटल 2.0 और अन्य प्रस्तावित आईटी अनुप्रयोगों के तहत आगामी डिजिटल व्यापार विकास गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग को रोक दे।% एचडीएफसी बैंक ने कहा कि इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल से कहा गया है कि वे कमियों की जांच करें और जवाबदेही तय करें।

समग्र व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा- एचडीएफसी

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उसने अपने आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं और शेष काम को तेजी से पूरा करेगी। बैंक ने कहा है कि वह डिजिटल बैंकिंग चैनलों में हालिया परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और उम्मीद जताई की उसके मौजूदा क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और मौजूदा परिचालन पर ताजा नियामकीय फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक का मानना है कि इन उपायों से उसके समग्र व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

देश में बिक रहा मिलावटी शहद! डाबर, पतंजलि समेत कई बड़े ब्रांड्स के सैंपल हुए फेल

बिजनेस डेस्क।

भारत में बिकने वाले कई प्रमुख ब्रांड के शहद में चीनी शरबत की मिलावट पाई गई है, पर्यावरण नियामक सीएसई ने बुधवार को जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के खाद्य शोधकर्ताओं ने भारत में बिकने वाले प्रसंस्कृत और कच्चे शहद की शुद्धता की जांच करने के लिए 13 छोटे बड़े ब्रांड का चयन किया। इसने पाया कि 77 प्रतिशत नमूनों में चीनी शरबत की मिलावट थी। जांच किए गए 22 नमूनों में से केवल पांच सभी परीक्षण में सफल हुये।

डाबर ने दावे का किया खंडन

अध्ययन में कहा गया कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी और एपिस हिमालय जैसे प्रमुख ब्रांड के शहद के नमूने एनएमआर (न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस) परीक्षण में विफल रहे। इस का जवाब देते हुए, इमामी (झंडू) के प्रवक्ता ने कहा कि एक जिम्मेदार संगठन के रूप में इमामी सुनिश्चित करता है कि उसका झंडू शुद्ध शहद भारत सरकार और उसके प्राधिकरण एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित सभी नियम-शर्तों और गुणवत्ता मानदंडों / मानकों के अनुरूप हो और उनका पालन करे।' डाबर ने भी दावे का खंडन करते हुए कहा कि हालिया रिपोर्ट 'दुर्भावना और हमारे ब्रांड की छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रेरित' लगती है। उसने कहा है कि डाबर, शहद के परीक्षण के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सभी 22 मानदंडों का अनुपालन करती है।

हम प्राकृतिक शहद का करते हैं निर्माण- पतंजलि

डाबर ने कहा कि इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा अनिवार्य रूप से एंटीबायोटिक दवाओं की उपस्थिति के लिए डाबर शहद का भी परीक्षण किया जाता है। डाबर भारत में एकमात्र कंपनी है, जिसके पास अपनी प्रयोगशाला में एनएमआर परीक्षण उपकरण है, और उसी का उपयोग नियमित रूप से शहद का परीक्षण करने के लिए किया जाता है और भारतीय बाजार में बेचा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डाबर शहद 100 फीसदी शुद्ध हो। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, पतंजलि आयुर्वेद के प्रवक्ता एस के तिजारावाला ने कहा कि हम केवल प्राकृतिक शहद का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य नियामक एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हमारा उत्पाद एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट देश के प्राकृतिक शहद उत्पादकों को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह जर्मन तकनीक और महंगी मशीनरी को बेचने की साजिश है। यह देश के प्राकृतिक शहद उत्पादकों को बदनाम करने और प्रसंस्कृत शहद को बढ़ावा देने के लिए भी एक साजिश है।

सीएसई ने पहली बार इन ब्रांड के नमूनों का किया परीक्षण

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के कार्यकारी सदस्य देवव्रत शर्मा ने कहा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) परीक्षण में इस बात का भी पता मिल सकता है कि कोई खास शहद किस फूल से, कब और किस देश में निकाला गया है। इस परीक्षण में चूक होने की गुंजाइश नहीं है।' उन्होंने कहा, कि भारतीय खाद्य नियामक, एफएसएसएआई को अपने शहद के मानकों में एनएमआर परीक्षण को अनिवार्य कर देना चाहिये ताकि हमारे देशवासियों को भी शुद्ध शहद खाने को मिले। गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) में सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड (सीएएलएफ) में पहली बार सीएसई द्वारा इन ब्रांड के शहद के नमूनों का परीक्षण किया गया। परीक्षणकर्ता, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, लगभग सभी शीर्ष ब्रांड, शुद्धता के परीक्षणों में सफल हुए, जबकि कुछ छोटे ब्रांडों में सी-4 चीनी का पता लगने से वे परीक्षणों को विफल रहे। सी-4 ऐसी बुनियादी मिलावट का प्रारूप है जिसमें गन्ना चीनी का उपयोग किया जाता है।

मिलावटी शहद पहुंचा सकता है नुक्सान

परीक्षणकर्ता ने कहा कि जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) का उपयोग करके उन्हीं ब्रांडों के नमूनों का परीक्षण किया गया - तो लगभग सभी छोटे बड़े ब्रांड परीक्षण में विफल पाये गये। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) परीक्षण में किसी भी प्रकार की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। मिलावट की पक्की जांच के लिए विश्व स्तर पर एनएमआर परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है। इस एनएमआर परीक्षण में 13 ब्रांडों के परीक्षणों में से केवल तीन सफल हो पाये। यह परीक्षण, जर्मनी में एक विशेष प्रयोगशाला द्वारा किया गया था।

रिलायंस जियो की गेमिंग मार्केट पर नजर, सेन फ्रांसिस्को की कंपनी क्रिकी में किया निवेश

बिजनेस डेस्क।

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने सैन फ्रांसिस्को की मोबाइल गेमिंग कंपनी क्रिकी में निवेश किया है। रिलायंस जियो ने हालांकि निवेश की कुल रकम का खुलासा नहीं किया है। क्रिकी ने अब तक कुल मिलाकर 2.20 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है। भारत में क्रिकी ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर संवर्धित रियलिटी आधारित 'यात्रा' नाम का एक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। रिलायंस जियो के ग्राहकों को इस नए गेम के 3डी अवतार के साथ खेलने की विशेष सुविधा मिलेगी।

गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा

सभी मोबाइल उपभोक्ता इस गेम को खेल सकेंगे। गेम को गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। देश में गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अगले वर्ष तक देश में गेमिंग इंडस्ट्री के करीब 100 अरब रुपये का आंकड़ा छू लेने का अनुमान है जो 2022 तक 143 अरब रुपये तक पहुंच सकता है। रिलायंस जियो गेमिंग मार्केट में अपने कदम मजबूती से जमाना चाहती है और क्रिकी में निवेश को इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

दुनिया के सर्वोत्तम अनुभवों को भारत लाना

रिलायंस जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने एक बयान में कहा क्रिकी, भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी को ऑगमेंटेड रियलिटी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा विज़न दुनिया भर के सर्वोत्तम अनुभवों को भारत लाना है। 'यात्रा' गेम इस दिशा में एक कदम है। ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग, इस्तेमाल करने वालों को अपनी ही तरह की एक नई दुनिया में ले जाता है। हम जियो और अन्य उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे 'यात्रा' गेम के माध्यम से ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव करें।

काल्पनिक दुनिया को सीधे आपके घर तक पहुंचाएंगे

गेम लॉन्च के मौके पर क्रिकी के संस्थापक जाह्नवी और केतकी श्रीराम ने कहा, 'क्रिकी में काल्पनिकता और वास्तविकता को एक साथ लाना ही हमारा विज़न है। ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से हम काल्पनिक दुनिया को सीधे आपके घर तक पहुंचाएंगे और वो भी आपके मोबाइल फोन के जरिए।'

सेंसेक्स 37 अंक फिसला, निफ्टी में पांच अंक की मामूली बढ़त

मुम्बई: विदेशी बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच मुनाफावसूली और बैंकिंग तथा वित्तीय समूह की कंपनियों में हुई बिकवाली के दबाव में बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 37.40 अंक फिसलकर 44,618.04 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी हालांकि गेल और ओएनजीसी जैसी दिग्गज कंपनियों में हुई लिवाली के दम पर लाल निशान में जाने से बच गया और कल के मुकाबले 4.70 अंक की बढ़त में 13,113.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज बढ़त में 44,729.52 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 44,729.64 अंक के दिवस के उच्चतम और 44,169.97 अंक के दिवस के निचले स्तर के बीच रहा। अंत में यह गत दिवस की तुलना में 0.08 प्रतिशत लुढ़ककर 44,618.04 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियां हरे निशान में और आठ लाल निशान में रहीं। रिएल्टी सहित बीएसई के 18 समूह के सूचकांक भी आज तेजी में रहे और मात्र बैंकिंग और वित्तीय समूह की कंपनियों के सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी भी बढ़त में 13,121.40 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 13,128.50 अंक के दिवस के उच्चतम और 12,983.55 अंक के दिवस के निचले स्तर से होता हुआ गत दिवस की तुलना में 0.04 प्रतिशत यानी 4.70 अंक की बढ़त में 13,113.75 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 36 कंपनियां गिरावट में और 13 तेजी में रहीं जबकि एक कंपनी के शेयरों के दाम स्थिर बंद हुए। गेल, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया और टाइटन के शेयरों में आज सर्वाधिक तेजी दर्ज की गयी। विदेशी बाजारों में आज मिश्रित रुख देखा गया। ब्रिटेन में दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सरकार की मंजूरी मिलने का असर बाजार पर भी दिखा। शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन के एफटीएसई में 0.14 प्रतिशत की तेजी देखी गई जबकि जर्मनी का डैक्स 0.22 प्रतिशत लुढ़क गया। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.58 प्रतिशत और जापान का निक्केई 0.05 प्रतिशत चढ़ कर बंद हुआ जबकि हांगकांग का हैंगशैंग 0.13 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.07 प्रतिशत की गिरावट में बंद हुआ।

चीन में इंटरनेट प्लस पर्यटन का तेज विकास

बीजिंग।

ताशी डिंगजेन एक तिब्बती जातीय लड़का है। उसका जन्म वर्ष 2000 में हुआ और अब चीन के सछ्वान प्रांत के कानची प्रिफेक्चर की लीथांग काउंटी में रहता है। हाल में डिंगजेन की भागीदारी से कानची प्रिफेक्चर का सांस्कृतिक और पर्यटन प्रचार वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसका नाम है डिंगजेन की दुनिया। वीडियो में दिखाया गया है कि डिंगजेन हर दिन द्वार खोलकर बर्फीले पहाड़ के सुंदर दृश्यों का आनंद उठाता है और पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर पठार पर सरपट दौड़ता है। वीडियो में सुंदर दृश्य बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं। डिंगजेन जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड आदि देशों में भी प्रसिद्ध बन गया। आंकड़ों के अनुसार पर्यटन बाजार में लीथांग काऊंटी लोकप्रिय होने लगी है। नवंबर के अंत तक लीथांग से जुड़े सर्च में 620 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके चलते कानची प्रिफेक्चर का पर्यटन भी लोकप्रिय होने लगा।

आंकड़ों के अनुसार 25 नवंबर तक कानची में होटल रिजर्व करने की संख्या पिछले साल की इसी अवधि से 89 प्रतिशत अधिक रही। इस साल कानची प्रिफेक्चर की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। 15 नवंबर से अगले साल 1 फरवरी तक सिलसिलेवार उदार नीति लागू हो रही है। जैसा कि पर्यटक कानची में 67 ए-स्तरीय पर्यटन स्थलों में बिना टिकट घूम सकते हैं और तीन हवाई अड्डे जाने के हवाई टिकट में 90 प्रतिशत की छूट मिलती है। बताया जाता है कि डिंगजेन का जन्मस्थान लीथांग काऊंटी इस साल फरवरी में गरीबी से बाहर निकली। पर्यटन का विकास गरीबी उन्मूलन का मुख्य कदम है। पर्यटन उद्योग का विकास करने के लिए स्थानीय सरकार ने घुड़सवारी त्योहार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। डिंगजेन के एकदम प्रसिद्ध होने से भी इंटरनेट प्लस पर्यटन की विशाल संभावना साबित हुई है। वास्तव में इंटरनेट प्लस पर्यटन एक नया शब्द नहीं है। महामारी के बाद के युग में पर्यटन उपभोग की मांग इकट्ठा हो रही है। इस साल पर्यटन के डिजिटलीकरण के विकास में नए अवसर पैदा हुए। इंटरनेट के साथ मिश्रित पर्यटन बाजार का तेज विकास हो रहा है। 30 नवंबर को चीनी संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग आदि दस विभागों ने इंटरनेट प्लस पर्यटन से पर्यटन उद्योग का उच्च गुणवत्ता वाला विकास बढ़ाने के बारे में राय जारी की।

पॉडकास्ट नेटवर्क वंडरी को खरीदने पर अमेजन की बातचीत जारी : रिपोर्ट

सैन फ्रांसिस्को।

अमेजन की योजना कथित तौर पर पॉडकास्ट स्टार्टअप वंडरी को खरीदने की बताई जा रही है और इसी के साथ कंपनी ऑडियो सेक्टर में भी अपने पैर पसारने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस विषय के जानकार लोगों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि वंडरी की कीमत तीस करोड़ डॉलर बताई जा रही है, जबकि साल 2019 के जून में कंपनी की कीमत दस करोड़ डॉलर आंकी गई थी। वंडरी इस साल चार करोड़ डॉलर अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश में है। कंपनी की लगभग 75 फीसदी कमाई विज्ञापनों से होती है, जबकि बाकी की कमाई टीवी और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की लाइसेंसिंग से होती है। साल 2016 में वंडरी को लॉन्च किया गया था। डॉ. डेथ, डर्टी जॉन, बिजनेस वॉर्स, द श्रिंक नेक्स्ट डोर और ग्लेडिएटर जैसे अपने शोज के माध्यम से यह दर्शकों का दिल जीत चुकी है। यह वंडरी के लिए एक आखिरी बड़ा मौका हो सकता है, जिसके तहत वह अमेजन जैसी किसी बड़ी कंपनी द्वारा अधिग्रहण किए जाने के साथ पॉडकास्टिंग के बढ़ते बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बना सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

900 दिन बाद आरएफ कैप में दिखेंगे रोजर फैडरर

नई दिल्ली । लगभग ढाई साल के बाद रोजर फेडरर अपने प्रसिद्ध आरएफ लोगो के मालिक बन गए हैं। हाले 2018 में फेडरर ने अपना आखिरी मैच खेला जिसमें उन्होंने अपने लोगो वाली टोपी पहनी थी। लेकिन कुछ सप्ताह बाद ही विंबलडन सेंटर कोर्ट में प्रवेश करते ही उन्होंने लोगो के उपयोग के अधिकार नाइके से गंवा लिए थे। रोजर ने अब अपने प्रशंसकों के साथ खुशखबरी साझा की है वह जल्द नए कलेक्शन के साथ वापस आ रहे हैं। आगामी दिनों में रोजर फेडरर की टोपी आठ रंगों में सामने आएगी। बता दें कि इस लोगो के साथ रोजर ने अपना आखिरी मैच लगभग 900 दिन पहले बोर्ना कॉरिक के खिलाफ खेला था। इसमें वह फाइनल हार गए थे। इसके बाद उन्होंने इसे कभी नहीं पहना। लेकिन 2021 में सब बदल जाएगा जब वह घुटने की चोट के बाद कोर्ट पर वापसी करेंगे।

आईएसएल-7

जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी चेन्नइयन एफसी

गोवा।

पूर्व चैम्पियन चेन्नइयन एफसी शुक्रवार को बोम्बोलिम के जीएमसी स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ होने वाले मुकाबले को जीतकर हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। सीजन के अपने पहले मैच में जमशेदपुर एफसी के खिलाफ 2-1 की जीत दर्ज करने के बाद कोच कसाबा लाजलो की टीम चेन्नइयन को केरला ब्लास्टर्स के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेलकर अंक बांटना पड़ा था। जहां एक तरफ बेंगलुरु की टीम इस सीजन में लगातार दो ड्रॉ खेलकर अपनी पहली जीत की तलाश में है, तो वहीं चेन्नइयन के पास इस मैच को जीतकर तीन अंक लेने का मौका होगा। लाजलो ने भले हाल ही में ही चेन्नइयन के साथ अपने कार्यकाल की शुरुआत की हो, लेकिन इस मैच ने अपना महत्व नहीं खोया है। लाजलो ने कहा, यह एक स्पेशल मैच है और हमारे लिए यह एक डर्बी की तरह है। इस मैच को जीतने के लिए हम हरसंभव कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम तीन अंक हासिल करते हैं तो तालिका में हम अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। चेन्नइयन की डिफेंस ने लीग के इतिहास में इस बार अब तक शानदार शुरुआत की है और उसने अपने पहले दो मैचों से अब तक केवल एक ही गोल खाया है।दूसरी तरफ, बेंगलुरु के कोच कार्लेस कुआड्रार्ट के लिए कई सारी समस्याएं हैं। उनकी टीम आक्रमण करने के लिए संघर्ष कर रही है। बेंगलुरु ने अपने पिछले दो मैचों में केवल 12 शॉट लिए हैं और उसमें से वह तीन ही शॉट को टारगेट पर लिया है। उनके तीन मुख्य खिलाड़ी सुनील छेत्री, क्लाइटन सिल्वा और क्रिस्टियन ओप्सेथ अब तक आक्रमण करने में विफल रहे हैं।कुआड्रार्ट ने कहा, डिफेंस में टीम काफी निरंतरता दिखा रही है। मुझे लगता है कि हमारे पास गोवा के खिलाफ मैच में एक पल था जहां हमें थोड़ा नुकसान हुआ। यहीं पर दूसरी टीमों ने गोल किया। हमने अन्य टीमों के आक्रमण को नियंत्रित किया और हैदराबाद के खिलाफ भी यही था। दोनों मैचों में विपक्षी टीम मौके नहीं बना रही थी। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि हमें कहां सुधार करना

है और हम इस पर काम कर रहे हैं।

महिला फुटबॉल को आगे ले जाने के प्रयासों से प्रभावित हूं : आशालता

नई दिल्ली।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान आशालता देवी ने कहा है कि वह महिला फुटबॉल को आगे ले जाने के प्रयासों से काफी प्रभावित हैं। आशालता का मानना है कि हाल के दिनों में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने मुकाबले आयोजित कराए हैं उससे टीम के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। आशालता ने कहा- पिछले दो-तीन वर्षों में हमने कई मुकाबले खेले और जब हम कॉटिफ कप के लिए स्पेन गए तो हमें वहां सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिला। ऐसे कठिन मुकाबलों में खेलने से हमें हमारे प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिली। मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए एआईएफएफ और महिला समिति की शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा- पहले हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते थे लेकिन अब हम इसे जानते हैं।

हमारी कोच मयमॉल ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चोट से बचने और वीडिया विश्लेषण से अवगत कराया। आशालता ने कहा- फीफा अंडर-17 विश्वकप और एएफसी महिला एशिया कप 2022 से लोगों को भारत में महिला फुटबॉल को जानने का मौका मिलेगा। महिला फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए एआईएफएफ ने जो प्रयास किए हैं इससे लोगों को उसे पहचानने में मदद मिलेगी।

पुरुष चैम्पियंस लीग में पहली महिला रेफरी बनी स्टेफेनी

तुरीन। स्टेफनी फ्रैपपार्ट यूईएफए चैम्पियंस लीग के पुरुष मैच में रैफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं। स्टेफनी ने बुधवार रात को जुवेंतस और डायनामो कीव के बीच एलियांज स्टेडियम में खेले गए मैच में रेफरी की भूमिका निभाई थी। इस मैच में जुवेंतस ने 3-0 से जीत हासिल की। यूईएफए ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, बुधवार रात, स्टेफनी फ्रैपपार्ट यूसीएल मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाले पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने जुवेंतस और डायनामो कीव के मैच में रैफरी की भूमिका निभाई। बधाई स्टेफनी। फीफा महिला विश्व कप के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, आप इसे देखकर काफी खुश होंगे। स्टेफनी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने पुरुष चैम्पियंस लीग के मैच में रेफरी का राल अदा किया। इससे पहले 2019 में वह पहली महिला बनी थीं जिसने यूरोप में पुरुष फुटबाल मैच में रेफरी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने यूईएफए सुपर कप में लिवरपूल और चेल्सी के मैच में बतौर रेफरी के तौर पर शिरकत की थी।

बीसीसीआई प्रथम श्रेणी अनुबंध में जोड़ सकती है प्राकृतिक आपदा संबंधी अनुच्छेद

नई दिल्ली।

बीसीसीआई अगर उन सभी प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के लिए अनुबंध लाने का फैसला करती है जो कोविड-19 के कारण 2020-21 सीजन को लेकर अनिश्चित्ता के चलते मैच फीस से हाथ धो बैठेंगे, तो वह इसमें फोर्स मैशेयुर क्लॉज यानी प्राकृतिक आपदा संबंधी अनुच्छेद शामिल कर सकती है। कोविड-19 के कारण 2020-21 सीजन को लेकर अनिश्चितता है, जिसने खिलाड़ियों की मैच फीस को संकट में डाल दिया है। अभी तक ऐसी संभावनाएं हैं कि इस सीजन जनवरी से सिर्फ सीमित ओवरों के टूर्नामेंट ही हो सकते हैं। खिलाड़ियों के नुकसान की भरपाई किए जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बोर्ड अभी यह नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समय खिलाड़ियों के पास अनुबंध नहीं हैं। सिर्फ उत्तराखंड और पंजाब राज्य संघों ने इस समय अनुबंध के बारे में सोचा है, हालांकि इस योजना पर अभी काम किया जा रहा है। मामले से संबंध रखने वाले एक अधिकारी ने बताया, अगर प्रथम श्रेणी, रणजी ट्रॉफी, पुरुष और महिला खिलाड़ी के लिए अनुबंध सिस्टम होता तो हां, बीसीसीआई और शीर्ष परिषद भरपाई के बारे में सोचते। उनको भुगतान किया जा सकता था, क्योंकि वह स्थिति के कारण परेशान हैं, लेकिन अनुबंध नहीं हैं। बीसीसीआई राज्य संघों के साथ मिलकर प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के लिए अनुबंध सिस्टम ला सकती है, यह एक संयुक्त प्रयास हो सकता है।अधिकारी ने कहा, बीसीसीआई सभी प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के लिए अनुबंध सिस्टम ला सकती है। यह बीसीसीआई और राज्य संघों का संयुक्त प्रयास भी हो सकता है, लेकिन यह देखना होगा कि यह 50-50 होगा या 70-30, 80-20। अनुबंध में हालांकि फोर्स मेशुयर क्लॉज यानी प्राकृतिक आपदा संबंधी अनुच्छेद को शामिल किया जा सकता है, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी के लिए जगह होगी। अधिकारी ने कहा, फोर्स मेशुयर हमेशा है। आप विपदाओं के बारे में पता नहीं लगा सकते। सभी तरह के नियम हैं और यह इस बात पर निर्भर है कि आप इसे कैसे लागू करते हैं। बुनियादी बात यह है कि क्रिकेटरों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए, ताकि वह संघर्ष न करें, और क्रिकेट पर ध्यान दें। इस समय किसी तरह की क्रिकेट नहीं हो रही है इसलिए भुगतान करना मुश्किल है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हालांकि कहा था कि जनवरी-2021 में घरेलू सीजन की शुरुआत होगी। इस पर अभी भी सवालिया निशान हैं और बोर्ड की तरफ से राज्य संघों को भी कार्यक्रम को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बड़ौदा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ जैसे कई राज्यों ने सीजन की तैयारी करना शुरू कर दी है। वह इस दौरान कोविड-19 से संबंधित एसओपी का ख्याल रख रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

मेरा उद्देश्य टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना : जरमनप्रीत सिंह

बेंगलुरु। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर जरमनप्रीत सिंह का मानना है कि टीम के प्रत्येक सदस्य आने वाले कुछ महीनों में टूर्नामेंट्स को लेकर उत्साहित हैं। 2016 के रियो ओलंपिक के बाद से पिछले चार वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी ने खूब तरक्की की है। भारत विभिन्न टूर्नामेंटों में पदक जीतकर एफआईएच विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर चढ़ गया है। टीम की स्थिति पर 24 साल के जनमनप्रीत ने कहा- मुझे लगता है कि अपने आप में भारत के लिए खेलना मेरे लिए एक सपना सच था, लेकिन अपने पहले दो टूर्नामेंट में बैक-टू-बैक पदक जीतना एक ऐसी कहानी है जिसे मैं एक दिन अपने पोते को बता सकता हूं। मुझे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उच्चतम स्तर पर देश और पदक भी जीते हैं, इसलिए यह मुझे वास्तविक खुशी देता है। जरमनप्रीत ने कहा- मेरा उद्देश्य हमेशा टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि मेरा कोच मुझसे क्या करने के लिए कह रहा है। मुझे पता है कि अगर मैं उन चीजों को करने में सक्षम हूं, तो हम एक टीम के रूप में वास्तव में सफल होंगे।

टोक्यो ओलंपिक में टीम के पास आगे बढ़ने का अच्छा मौका : जरमनप्रीत

बेंगलुरू।

पिछले दो वर्षों से भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे डिफेंडर जरमनप्रीत सिंह अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने पर ध्यान लगाए हुए हैं। जरमनप्रीत ने कहा, मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी टीम में जो कुछ होने वाला है, उसे लेकर हर कोई उत्साहित है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब टीम वहां जाए और पदक जीते तो मैं उस टीम का हिस्सा रहूं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हॉकी इंडिया ने मुझ जैसे खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करने के लिए एक असाधारण काम किया है और अब मैं मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देकर उनका समर्थन चुकाना चाहता हूं। साथ ही, मेरा यह भी मानना है कि टोक्यो ओलंपिक में टीम के पास आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम पर ही होगा। जरमनप्रीत ने 2018 में सीनियर टीम के साथ पदार्पण किया था और वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 2018 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक जीता था।

उन्होंने भारतीय टीम के साथ अपने शुरुआत दिनों को लेकर

कहा, मुझे लगता है कि भारत के लिए खेलना अपने आप में एक सपना था, जोकि सच हुआ। लेकिन मेरे पहले दो टूर्नामेंटों में लगातार पदक जीतने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपनी इस कहानी को अपने पोतों को (हंसते हुए) भी सुना सकता हूं।

यह इंग्लैंड टीम किसी को भी हरा सकती है - बेन स्टोक्स

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका को टी-20 सीरीज में उसके घर में ही 3-0 से मात देने के बाद हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने कहा है कि इंग्लैंड की मौजूदा टीम अपनी पूरी ताकत के साथ खेले तो विश्व की किसी भी टीम को हरा सकती है। स्टोक्स ने कहा, हम जब एक साथ कुछ मैच खेलते हैं तो यह सोचना डरवाना सा है कि यह टीम कहां तक जा सकती है। हाल ही में खेली गई टी-20 सीरीज एक उदाहरण है, जहां इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंग्थ टीम खेली, क्योंकि इस समय किसी तरह की फ्रेंचाइजी लीग में उसके खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। न ही टीम इस समय किसी तरह की चोटों से परेशान है। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पहले मैच में पांच विकेट, दूसरे मैच में चार विकेट और तीसरे मैच में नौ विकेट से मात दी थी। स्टोक्स ने कहा, एक टीम के तौर पर हम अपनी टीम की काबिलियत को लेकर काफी आत्मविश्वासी हैं। हमने जो हमेशा किया है वो है अपने आप पर ध्यान देना। हम दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं- उनकी मजबूती, कमजोरियों पर- लेकिन हम जो बहुत अच्छे से करते हैं वो है अपने आप पर ध्यान देना। स्टोक्स ने कहा, हम जानते हैं कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, यह कहना कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। हम इसी स्थिति में हैं। हम जानते हैं कि यह टीम कितनी मजबूत है। इस टीम का हिस्सा होना शानदार है। इंग्लैंड को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो रही है।

डु प्लेसिस को वनडे सीरीज में आराम

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका ने सीनियर बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। डु प्लेसिस के अलावा कागिसो रबादा, पीटे वान बिलजोन, बजोर्न फॉरट्यूइन और रीजा हैंड्रिक्स को भी आराम देने का फैसला किया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने एक बयान में कहा, इन खिलाड़ियों को टीम से रिलीज कर दिया गया है, ताकि वह अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ सीएसए के चार दिवसीय घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगे या आराम कर सकें। इन खिलाड़ियों में फाफ डु प्लेसिस (आराम), कागिसो रबादा (चोट रीहैब), पीटे वान बिलजोन, बीजोर्न और रीजा हैंड्रिंग्स (चार दिवसीय घरेलू सीरीज) के नाम शामिल हैं।डु प्लेसिस ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में तीन मैचों की टी-20 सीरीज में हिस्सा लिया था। उन्होंने कुल 121 रन बनाए थे।

टीम : क्विंटन डी कॉक (कप्तान/विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा, जूनियर डाला, बेयुरान हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, जानेमन मलान, डेविड मिलर, लुंगी नगिदी, एनरिक नॉर्टजे, आंदिले फेहुल्कवायो, तबेरज शम्सी, लुथा सिपाम्ला, जोन-जोन स्मट्स, ग्लेंटन स्टुरमैन, रासी वान डर डुसैन, काइल वैरीयेने।

माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए मेसी ने शर्ट उतारी, नियम टूटा, लगा जुर्माना

बार्सीलोना । डिएगो माराडोना को श्रृद्धांजलि देने के लिये अपनी जर्सी उतारने वाले लियोनेल मेस्सी पर 600 यूरो (720 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। स्पेनिश फुटबॉल महासंघ की प्रतिस्पर्धा समिति ने रविवार को स्पेनिश लीग में ओसासुना पर बार्सीलोना की 4-0 से जीत के बाद यह जुर्माना लगाया। अर्जेंटीना के स्टार मेस्सी ने गोल करने के बाद बार्सीलोना की जर्सी उतारकर माराडोना के पुराने क्लब नेवेल्स ओल्ड ब्वायज की जर्सी पहनी। इसके बाद दोनों हाथ आसमान में उठाकर चुंबन दिया। मैच के बाद मेस्सी ने अपनी इस तस्वीर के साथ माराडोना की तस्वीर पोस्ट करके लिखा- फेयरवेल , डिएगो। माराडोना का पिछले सप्ताह दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया था। महासंघ ने बार्सीलोना पर भी 180 यूरो का जुर्माना किया । मेस्सी को इसके लिये पीला कार्ड भी देखना पड़ा । वह और क्लब इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

कैनबरा टी-20 : आखिरी वनडे में जीत से बढ़ा भरोसा, अतीत के दम पर उतरेगी भारत

कैनबरा।

तीसरे और आखिरी वनडे में सम्मानजनक जीत हासिल करने बाद भारतीय टीम शुक्रवार को मनुका ओवल मैदान से आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज करेगी। आस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। शुरुआती दो मैचों में जीत हासिल करने के बाद आस्ट्रेलिया को मनुका ओवल मैदान पर खेले गए तीसरे वनडे में हार मिली थी। भारत ने आस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया था और इस जीत से उसका आत्मविश्वास ऊपर होगा। टीम की जीत में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले शार्दूल ठाकुर हालांकि इस मैच में नहीं खेलेंगे। टीम प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि जो खिलाड़ी सिर्फ टी-20 सीरीज के लिए चुने गए हैं, वही इस सीरीज में खेलेंगे। इसका मतलब है कि ठाकुर के अलावा 57 रन देकर एक विकेट लेने वाले स्पिनर कुलदीप यादव और बतौर सलामी बल्लेबाज 39 गेंदों पर 33 रन बनाने वाले शुभमन गिल भी इस सीरीज में तब तक नहीं खेल पाएंगे, जब तक कोई खिलाड़ी चोटिल न हो।ठाकुर, कुलदीप और गिल वनडे टीम में चुने गए थे। आस्ट्रेलिया में हालांकि भारत का टी-20 रिकार्ड अच्छा है। भारत ने अभी तक आस्ट्रेलिया में नौ मैच खेले हैं, जिसमें से पांच बार भारत को जीत मिली है। आस्ट्रेलिया तीन बार जीती है, जबकि एक मैच का परिणाम नहीं निकल सका था। एक अहम बात यह है कि भारत ने आस्ट्रेलिया में कभी भी टी-20 सीरीज नहीं गंवाई है।भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले वनडे में मिली हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों की टी-20 मोड से वनडे मोड में न आने को लेकर आलोचना की थी। ठाकुर ने भी बुधवार को माना कि दोनों प्रारूप काफी अलग हैं। आस्ट्रेलिया और भारत दोनों खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि खिलाड़ी 48 घंटों के भीतर कैसे वनडे से अपने आप को टी-20 प्रारूप के ढालते हैं। खिलाड़ियों ने हालांकि एक महीने पहले ही आईपीएल का लंबा सीजन खेला था, लेकिन तीन मैचों की वनडे सीरीज ने उन्हें 50 ओवरों के प्रारूप में ढाल दिया।ठाकुर ने अलग-अलग प्रारूपों में रमने को लेकर आने वाली मुश्किलों के बारे में कहा था, निश्चित तौर पर यह मुश्किल है। यह अलग प्रारूप है और 50 ओवरों में अलग तरह की क्रिकेट खेली जाती है। खेल काफी तेजी से शुरू होता है। 10 ओवर का पावरप्ले होता है। फिर यह मध्य में धीमा होता जाता है इसके बाद आप फिर 35-40 ओवरों में बल्लेबाजी तेजी से रन बनाते हुए देखते हैं। 40 ओवरों के बाद पाबंदियां खत्म हो जाती हैं और आपके पास घेरे के बाहर एक और फील्डर होता है। इसलिए मैच ऊपर-नीचे होता रहता है।

भारत के पास हालांकि टी-20 के लिए अलग टीम है, लेकिन 16 में से 14 खिलाड़ी वही हैं जो वनडे टीम में थे। दीपक चहर और वॉशिंगटन सुंदर टी-20 टीम का हिस्सा हैं।

टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन अधिक महिलाओं को हॉकी लेने के लिए प्रेरित करेगा : रजनी

बेंगलुरु । भारतीय महिला हॉकी टीम में अनुभवी गोलकीपर रजनी एतिमार्पू को लगता है कि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में अगर अच्छे नतीजे आए तो इससे देश में महिला खिलाड़ियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। रानी के नेतृत्व वाली टीम ने 2019 में एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर जीतकर लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों के लिए एक बर्थ हासिल की। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब टीम बैक-टू-बैक ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहीं रजनी ने कहा- टोक्यो ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने से निश्चित रूप से खेल की प्रोफ़ाइल उठेगी और यह निश्चित रूप से अधिक महिलाओं को हॉकी लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भारतीय महिला हॉकी ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से जो मान्यता प्राप्त की है, उससे खेल में महिलाओं की भागीदारी पहले ही बढ़ गई है और हम निश्चित हैं कि हमारे अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अधिक महिलाओं को लगेगा कि हॉकी एक व्यवहार्य करियर विकल्प हो सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोशल मीडिया (Social Media) पर बॉलीवुड (Bollywood) की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) और निक जोनस (Nick Jonas) दोनों ही काफी एक्टिव रहते हैं. इस खास मौके पर दोनों ने एक-दूसरे के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स को सामने रखा.

प्रियंका निक ने शादी के दूसरी एनिवर्सरी पर एक-दूसरे को किया WISH, लिखा स्पेशल पोस्ट

प्रियंका चोपड़ा जोनास और निक जोनस की शादी को अब दो साल पूरे हो गए हैं. शादी की दूसरी सालगिरह. के मौके पर दोनों को सोशल मीडिया पर खूब बधाईयां मिली, लेकिन इस खास मौके को दोनों ने भी एक-दूसरे को बेहद खास अंदाज में बधाई दी. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा और निक दोनों ही काफी एक्टिव रहते हैं. इस खास मौके पर दोनों ने एक-दूसरे के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स को सामने रखा.

प्रियंका चोपड़ा जोनास ने शादी की दूसरी सालगिरह के मौके पर एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया. इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे का हाथ थामें सड़क किनारे चल रहे हैं. प्रियंका ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा- 'शादी के 2 साल पूरे होने की बधाई. हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया. आप मेरी ताकत हैं, कमजोरी हैं और सब कुछ हैं. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं.

निक जोनस (Nick Jonas) ने इस मौके पर प्रियंका को भी स्पेशल फील कराया. उन्होंने शादी की दो तस्वीरों को शेयर किया और कैप्शन लिखा- सबसे शानदार, खूबसूरत और इन्सपाइरिंग शख्स के साथ शादी के दो साल पूरे हुए. सालगिरह मुबारक हो प्रियंका. आई लव यू.

प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से 1 दिसंबर 2018 को शादी की थी. 2 दिसंबर, 2018 को प्रियंका और निक ने क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की. इसके अलावा रिसेप्शन पार्टीज समेत पूरे इवेंट की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

निक अमेरिकन म्यूजिशियन हैं. वहीं, प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द द व्हाइट टाइगरऔर वी कैन बी हीरोज में नजर आने वाली हैं. द व्हाइट टाइगरमें उनके साथ राजकुमार राव भी नजर आने वाले हैं.

'हवा कसूत्ती' पर किया सपना चौधरी ने जबर डांस, कहर बरपा रहा ये धमाकेदार Video

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर तहलका मचाते रहते हैं. उनके डांस के इतने दीवाने हैं कि उनका कोई भी वीडियो आते ही उसे कुछ ही मिनटों में हिट करा देते हैं. ऐसे में एक बार फिर सपना चौधरी का एक डांस वीडियो (Sapna Choudhary Dance Video) जबरदस्त वायरल हो रहा है. देश में ही नहीं विदेशों में भी सपना के काफी चाहने वाले है. सपना के चाहने वालों में हर उम्र के लोग है. लड़के हो या लड़कियां आज सभी सपना के दीवाने हैं.

सपना चौधरी के डांस वीडियो (Sapna Choudhary Dance Video) सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं. इन दिनों सपना का एक गाना यूट्यूब (Youtube) पर छाया हुआ है. 'हवा कसूत्ती (Hawa kakasuti)' गाने पर सपना का डांस लोग काफी पसंद कर रहे है. गाने में सपना चौधरी (Sapna Choudhary) का हमेशा की तरह देसी अंदाज नजर आ रहा है.

इस गाने में सपना के बेहतरीन मूव्स देखने मिल रहे हैं. इस हरियाणवी गाने को एंडी ढहिया (Andy Dahiya) ने लिखा है. वहीं, राजू पंजाबी और अन्नू कादयान ने इस गाने को गाया है. उनकी यह वीडियो देखकर आप खुद को डांस करने से नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

'सॉलिड बॉडी' गाने पर परफॉर्म करके लाइमलाइट में आईं सपना चौधरी के इस गाने को लाखों लोगों ने तब देखा था, जिसके बाद से वह सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थीं. वहीं, बिग-बॉस के घर में एंट्री लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ और इसके बाद से जैसे उनकी नई पारी शुरू हुई. बिग-बॉस के बाद सपना ने स्टेज शो के साथ ही वीडियो एल्बम में भी काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें उनके काम के लिए जमकर सराहा गया.

48 की उम्र में भी बेहद हॉट दिखती हैं कृष्णा अभिषेक की बीवी कश्मीरा शाह

अभिनेत्री और मॉडल कश्मीरा शाह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. 2 दिसंबर 1971 को जन्मी हैं.

फिल्मों में कश्मीरा को अधिक मौके नहीं मिल सके मगर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है.

अपने हॉट और बोल्ड अंदाज के चलते कश्मीरा अक्सर चर्चा में रहती हैं.

कश्मीरा के फैन्स उनके अभिनय और डांसिंग स्किल के साथ-साथ उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.

कश्मीरा और उनके पति कृष्णा अभिषेक की जोड़ी टीवी जगत की चर्चित जोड़ियों में शामिल है

कुछ दिन पहले कश्मीरा ने अपने एक फोटो शूट की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही थीं. इस तस्वीर को उनके पति कृष्णा ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था- जब आपको घर पर ही बिरयानी खाने को मिल जाए तो आप बाहर जाकर दाल मखनी क्यों खाएंगे ? मुझे तुम पर गर्व है कैश क्योंकि तुमने फिर से अपने हॉट अंदाज में वापसी की है.

कृष्णा और कश्मीरा की मुलाकात और पप्पू पास हो गया फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. उसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और साल 2013 में उन्होंने कृष्णा से शादी कर ली.

सनी देओल हुए कोरोना पॉजिटिव, मनाली से मुंबई जाने से पहले हुई पुष्टि

बॉलीवुड एक्टर और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गुरदासपुर सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को सनी देओल को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है. सनी निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश आए हैं, वह पिछले कुछ दिनों से कुल्लू जिले के मनाली में स्थिति फार्म हाउस में रुके हैं. 64 साल के एक्टर सनी देओल ने हाल ही में मुंबई में अपने कंधे की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद कुछ समय आराम करने के लिए मनाली में अपने फॉर्म हाउस पर आए.

जानकारी के मुताबिक, 3 दिसबंर को सनी देओल और उनके दोस्त मुंबई के लिए रवाना होने की योजना बना रहे थे. लेकिन हल्का बुखार और गले में खराश महसूस होने के बाद उन्होंने अपना कोविड 19 टेस्ट कराया, बताया जा रहा है कि मंगलवार को उनकी सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉ. देवेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है.

सनी देओल अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश आते-रहते हैं. वह मनाली की हसीन वादियों में अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं. कंधे की सर्जरी के बाद वह परिवार के साथ मनाली आए थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उनकी परिवार यहां से चला गया था. हालांकि, अब बॉलीवुड एक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. ऐसे में अभी उन्हें कुछ दिन अभी यहीं पर रुकना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि फिलहाल वह डॉक्टर्स की निगरानी में हैं.

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सत्ता छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चलाए हथौड़े, जानिए जाते-जाते दे रहे हैं कैसे जख्म

ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हार की वजह से जल्द ही व्हाइट हाउस से विदाई लेंगे। पूरे कार्यकाल में चीन के साथ कड़वाहट और टकराव रखने वाले ट्रंप जाते-जाते भी ड्रैगन को कई जख्म दे रहे हैं।

सत्ता छोड़ने से ठीक पहले ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से चीन को आगे भी काफी नुकसान हो सकता है।

बुधवार को ही ट्रंप प्रशासन ने चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए ट्रैवल वीजा पर रोक लगा दी तो सेना से संबंध रखने वाली कंपनी से कॉटन आयात को भी बंधुआ मंजदूरी का आरोप लगाकर बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं ट्रंप विदाई से पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स से एक बिल पास करा सकते हैं, जिससे चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी एक्सचेंज को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले बचे सात सप्ताह में ट्रंप चीन को और कैसे-कैसे जख्म देंगे। हॉन्ग-कॉन्ग की स्वायत्तता को कम करने के आरोपी अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं पर भी बैन लगाया जा सकता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ चाइन के अमेरिकन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर और चाइनीज सरकार के सलाहकार रेनमिन कहते हैं कि ट्रंप की ओर से उठाए जा रहे कदम बाइडेन के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, ''यह लगातार उकसावा है। बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु बढ़ता रहता है। अमेरिकी पक्ष के लिए तनाव से पहले के दौर लौटने की संभावना कम है।'' बाइडेन के लिए इन कदमों को या तो चीन के खिलाफ फायदा पहुंचाने वाली स्थिति या संभावित रूप से उनके हाथ बांधने के रूप में देखा जा सकता है। लंबे समय तक सीनेटर रहे और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसी सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि चीन के खिलाफ बड़े कदमों से पहले वह अमेरिका के सहयोगियों से राय-विचार लेंगे, जिसमें दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जनवरी में फेज वन ट्रेड डील पर दोबारा काम करना शामिल है। इस सप्ताह ट्रंप की ओर से उठाए गए कदम ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल कंप्टीशन और कोरोना महामारी की उत्पत्ति को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की वजह से खराब चल रहे रिश्तों को और बिगाड़ सकते हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने नवंबर में कहा था कि चीन के खिलाफ अमेरिका की सख्ती खत्म नहीं हुई है। उन्होंने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को 'मार्क्सवादी-लेनिनवादी राक्षस' बताते हुए क्रूर और मानवीय स्वतंत्रता के लिए खिलाफ होने का आरोप लगाया था। बुधवार को अमेरिकी संसद में उस कानून को पास किया गया जिससे यूएस अधिकारियों को चाइनीज कंपनियों के फाइनेंशल ऑडिट्स को जांचने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही कंपनियों को यह खुलासा करने की आवश्यकता होगी कि वे चाइनीज सरकार के नियंत्रण में हैं या नहीं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यॉरिटी ने यह भी कहा कि कस्टम अधिकारी चीनी सेना से जुड़ी कॉटन कंपनी के उत्पाद को लाने वाली जहाजों को जब्त कर लेंगे। यह कंपनी चीन की सबसे बड़ी कॉटन उत्पादक कंपनियों मं शामिल है।

नए वीजा नियमों के मुताबिक, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और उनके परिवार के लोगों को केवल सिंगल एंट्री वीजा दिया जाएगा, जोकि एक महीने तक ही वैध होगा। इससे पहले उन्हें मल्टीपल एंट्री विजिटर वीजा दिया जाता था और इसकी अवधि 10 साल तक होती थी।

अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने ईमेल से भेजे एक बयान में कहा, ''चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और इसके सदस्य अमेरिका में प्रोपेगैंडा, आर्थिक दबाव और अन्य कुटिल हरकतों से अमेरिकी लोगों को प्रभावित करने की

कोशिश करते हैं। दशकों तक हमने सीसीपी सदस्यों को अमेरिकी संस्थाओं और कारोबारों में मुक्त और बेरोकटोक पहुंच दिया, जबकि इस तरह की सुविधाएं अमेरिकी नागरिकों को चीन में नहीं दी गईं।'' उधर, बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि उन्हें वीजा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है। हालांकि, अमेरिका से उन्होंने रुख बदलने की अपील की। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ''चीन अमेरिकी पक्ष के साथ आपत्ति जाहिर करता है और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी लोग चीन के प्रति आम तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएंगे और सीसीपी के प्रति अपनी घृणा और असामान्य मानसिकता को छोड़ देंगे।''

आईएसआई के पूर्व प्रमुख बोले- ये कैसी सरकार है जो हमेशा अपने यूटर्न को सही ठहराने में लगी रहती है

इमरान खान सरकार की असलियत आई सामने

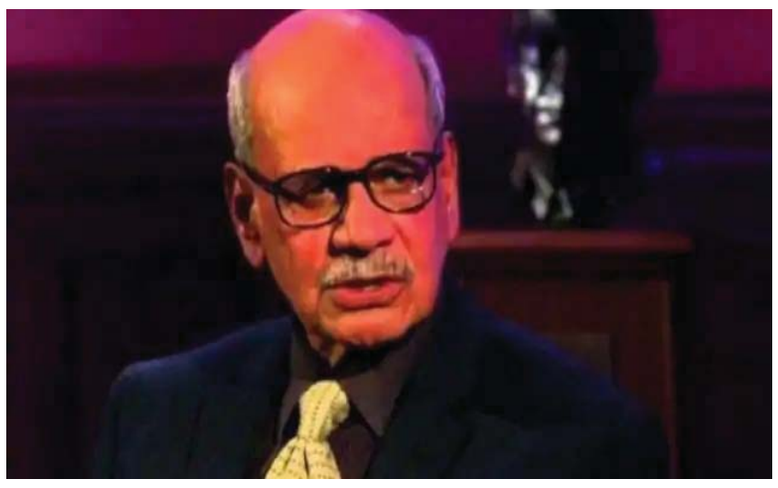

नई दिल्ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) असद दुर्रानी ने भारत को पाकिस्तान का पहला खतरा नहीं बताया है, उनका मानना है कि भारत से पाकिस्तान के लिए खतरे के रूप में हमेशा पहले नंबर पर नहीं रहा है।

दुर्रानी ने कहा कि हमें इंडिया से कोई खतरा नहीं है, अभी हमें शांत बैठना चाहिए। अगर वो बालाकोट जैसा कुछ करते हैं तो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। बीबीसी उर्दू को दिए अपने एक इंटरव्यू ने कहा, भारत अपनी ही चीजों में ऐसा हुआ है कि उसे पाकिस्तान की चिंता नहीं है। दूसरे बाहरी खतरों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान, सउदी अरब और तुर्की हमारे लिए नई चुनौती हैं।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरत के लिए असद दुर्रानी कहते हैं। यह बात पक्की है अंदरा का मामला हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, देश में आर्थिक अस्थिरता भी है। पाकिस्तान में सारी समस्याएं एक साथ ही आ गई हैं।

अफगानिस्तान की नीति

भारत से पाकिस्तान के खतरे पर जवाब देते हुए दुर्रानी कहते हैं कि भारत खतरे के तौर पर पाकिस्तान के लिए पहले नंबर पर नहीं रहा। पाकिस्तान के आंतरिक मामले भी बहुत है। अफगानिस्तान पर इस्तेमाल की जाने वाली हमारी नीति ने लोगों को अलग-थलग कर दिया।

दुर्रानी ने कहा, ऐसे कुछ लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर खफा हैं, बलूचिस्तान में सब ठीक नहीं है। सरकार की विश्वसनीयता पर बड़ा खतरा है। सरकार पर टिप्पणी करते हुए दुर्रानी ने कहा, ये कैसी सरकार है जो हमेशा अपने यूटर्न को सही ठहराने में लगी रहती है। मैं जब ऐसी बातें करता हूं तो लोग चिंता में आ जाते हैं। नैतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार भी एक बड़ी दिक्कत है। सब तरह की समस्याएं पाकिस्तान में इकट्ठा हो गई हैं।''

गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना कितना ठीक?

भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर कई समस्याएं खड़ी हो गईं। वहीं पाकिस्तान जो गिलगित बल्तिस्तान में बिना जमीनी सच्चाई जानें सूबे बनाने जा रहा है वो कितना सही है? पत्रकार के इस सवाल के जवाब में दुर्रानी कहते हैं,

मैंने कश्मीर को भी हैंडल किया है मेरा एक दोस्त कहा करता था कि अगर एक बार हम ऐसी गलती कर देते हैं तो हमारे कश्मीरी एजेंडे को बड़ा धक्का लगेगा।

दुर्रानी कहते हैं, ''कई चीज़ों का स्टेटस न बदलें क्योंकि जब भी राजनीतिक नंबर बनाने के लिए इसमें बदलाव होंगे तो हमें नुक़सान होगा। स्टेट ऑफ बेहावलपुर और स्टेट ऑफ स्वात बड़े अच्छे स्टेट थे। इन्हें मुख्यधारा में शामिल कर दिया और वही मुख्यधारा भ्रष्ट और नाकाम है। बलूचिस्तान के साथ भी हमने ऐसा ही किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे दुनिया के 100 नेता, कोरोना से लड़ाई पर होगा मंथन

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गुरुवार को करीब 100 विश्व नेता और कई दर्जन मंत्री कोविड -19 को लेकर अपने विचार रखेंगे कि महामारी से उबरने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। इस गंभीर कोरोना वायरस ने अब तक 1.5 मिलियन लोगों की जान ले ली है अमीर और गरीब देशों में लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। महासभा के अध्यक्ष Volkan Bozkir ने कहा कि कई टीकों को मंजूरी की खबर के साथ, इसके लिए दुनिया भर में अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं।

दुनिया नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर देख रही है। यह हमारे लिए एक परीक्षा है।

जब 2008 में वित्तीय बाजार ध्वस्त हो गए और दुनिया को बड़े संकट का सामना करना पड़ा, तब प्रमुख शक्तियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए एक साथ काम किया, लेकिन कोविड -19 महामारी के दौरान इसका उलटा हुआ है। किसी नेता ने महामारी को रोकने के लिए कोई एकजुट कार्रवाई नहीं की है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के 80 प्रतिशत के भागीदार दुनिया के सबसे अमीर देशों के 20 नेताओं को मार्च के अंत में एक पत्र भेजा था कि वे कोविड -19 से लड़ने के लिए युद्धकालीन योजना बनाएं और कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सहयोग करें। लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

जनरल असेंबली के प्रवक्ता ब्रेंडेन वर्मा ने बुधवार को कहा, इस विशेष बैठक का मुद्दा कोविड-19 की मुसीबत पर बहुपक्षीय और सामूहिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ठोस कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि महामारी के लिए वर्तमान में कई प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अब सभी देशों, संयुक्त राष्ट्र, निजी क्षेत्र और वैक्सीन डेवलपर्स को एक साथ लाने की जरूरत है।

अमेरिका में दिसंबर में ही दस्तक दे चुका था कोरोना, स्टडी में आया सामने

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका में एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि देश में संभवत: पिछले साल 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका था।

इस अध्ययन के तहत अमेरिकन रेड क्रॉस द्वारा एकत्रित नियमित रक्तदान के नमूनों का आकलन किया गया है। अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि 19 जनवरी, 2020 को हुई थी।

अमेरिका में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के श्रीधर वी वासवराजू और अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि 7,389 में से 106 नमूनों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रतिक्रियाशील एंडीबॉडीज पाई गई हैं।

क्लिनिकल इन्फेक्शस डिजीजेज पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार विशेष रूप से 84 नमूनों में सार्स-सीओवी-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने की गतिविधि पाई गई।

अनुसंधानकर्ताओं ने अध्ययन में लिखा, इन एंटीबॉडीज की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि सार्स-सीओवी-2 का संक्रमण अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में संभवत: पहले ही पहुंच गया था, जबकि इसका पता बाद में चला या फिर जनसंख्या के एक छोटे हिस्से में सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज थी।

अपनी इस शंका को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की एस1 सबयूनिट के संबंध में नमूनों की और अधिक विशिष्ट जांच की है। वैज्ञानिकों ने कहा, सार्स-सीओवी-2 का पता लगाने के लिए एस1 सबयूनिट पूरे स्पाइक प्रोटीन की तुलना में अधिक विशिष्ट एंटीजन है।

एससीओ की बैठक की मेजबानी करने पर सभी ने भारत की सराहना की: चीन

एजेंसी, बीजिंग। पहली बार एससीओ शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए भारत की चीन ने बुधवार को सराहना की।

चीन ने कहा कि सभी सदस्य देशों ने बैठक के परिणामों के बारे में खुलकर बात की और सम्मेलन के आयोजन के लिए नई दिल्ली की प्रशंसा की।

आठ सदस्यीय समूह में 2017 में शामिल होने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग सोमवार को हुई इस डिजिटल बैठक में शामिल हुए, जिसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बैठक की मेजबानी भारत द्वारा किए जाने और इसके परिणामों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सभी पक्षों ने परिणामों के बारे में खुलकर बात की और इस बैठक की मेजबानी के लिए भारत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार शासन प्रमुखों की परिषद की बैठक की मेजबानी की। यह वीडियो लिंक के माध्यम से आयोजित की गई और नेताओं ने इस बारे में बात की कि विभिन्न शिखर सम्मेलनों के परिणामों को किस तरह क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को कैसे मजबूत किए जाए तथा उनके बीच कई मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी।

चुनयिंग ने कहा कि एसीओ को आगे बढ़ाने के लिए चीन भारत तथा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

फाइजर को ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर दिया यह बयान

एजेंसी, नई दिल्ली। वैश्विक दवा कंपनी फाइजर ने गुरुवार को कहा कि भारत में फाइजर या बायोएनटेक का कोरोना टीका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपको बता दें कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने फाइजर या बायोएनटेक टीके के आकस्मिक इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी। ब्रिटेन के दवा नियामक मेडिसिंस एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेग्युलेटरी एजेंसी (एमएचआरए) ने कंपनी के टीके को अस्थायी मंजूरी दे दी है। यह टीका ब्रिटेन में अगले हफ्ते से उपलब्ध होगा। फाइजर के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा-अभी हम कई सरकारों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं, हम भारत में टीका उपलब्ध कराने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महामारी के दौर में फाइजर इस टीके को सिर्फ सरकारी अनुबंधों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी।

फाइजर की कोरोना वैक्सीन से फिलहाल भारत को नहीं है फायदा

ब्रिटेन, दवा कंपनी फाइजर-बायोएनटेक के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फिलहाल इस वैक्सीन से भारत को फायदा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ इसका करार नहीं हैं। ब्रिटेन की दवा और स्वास्थ्य उत्पाद नियामक एजेंसी (एमएचआरए) ने बताया कि यह टीका उपयोग में लाने के लिए सुरक्षित है। दावा किया गया था कि यह टीका कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 95 प्रतिशत तक असरदार रहा है। प्रमुख अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। इस टीके को फिलहाल बीएनटी162बी2 नाम दिया गया है।

चीन को लेकर जो बाइडेन सख्त, बोले- मैं आयात पर लगे शुल्क तुरंत नहीं हटाने वाला

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वह मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से होने वाले कई वस्तुओं के आयात पर लगाये गये शुल्क को तुरंत नहीं हटाने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा चीन के साथ किये गये प्रारंभिक व्यापार सौदे को भी वह फिलहाल रद्द नहीं करने वाले हैं। बाइडन का कहना है कि वह अमेरिका के भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के साथ भविष्य की बातचीत में अपने लाभ को अधिकतम रखना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार थॉमस फ्रडमैन से बात करते हुए बाइडन ने कहा, ''मैं कोई तात्कालिक कदम नहीं उठाने जा रहा हूं और शुल्क पर भी यही बात लागू होती है। बाइडन ने बुधवार को प्रकाशित फ्रीडमैन के आलेख में कहा है, ''मैं अपने विकल्पों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं करने जा रहा हूं।

खेलों पर महामारी का कैसा असर? आंद्रे अगासी और स्टेफी ग्राफ से बात

नई दिल्ली। खेलों पर महामारी का कैसा असर? आंद्रे अगासी और स्टेफी ग्राफ से बात लीडरशिप समिट 2020 का आज पांचवा दिन है। स्वाद से अब शिक्षा तक पहुंच गई है। मशहूर शेफ गगन आनंद और मैसिमो बोटुरा रितु डालमिया के साथ पकवान पर बेहद स्वादिष्ट चर्चा के बाद सेंट्रल स्क्वायर के संस्थापक आशीष धवन और इसरो के पूर्व चीफ कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति पर बात की। आखिरी सेशन में हमारे बीच अमेरिका के पूर्व टेनिस प्लेयर आंद्रे अगासी और जर्मनी की पूर्व टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इंसेफेलाइटिस लक्षण देखते ही हो जाएं सचेत

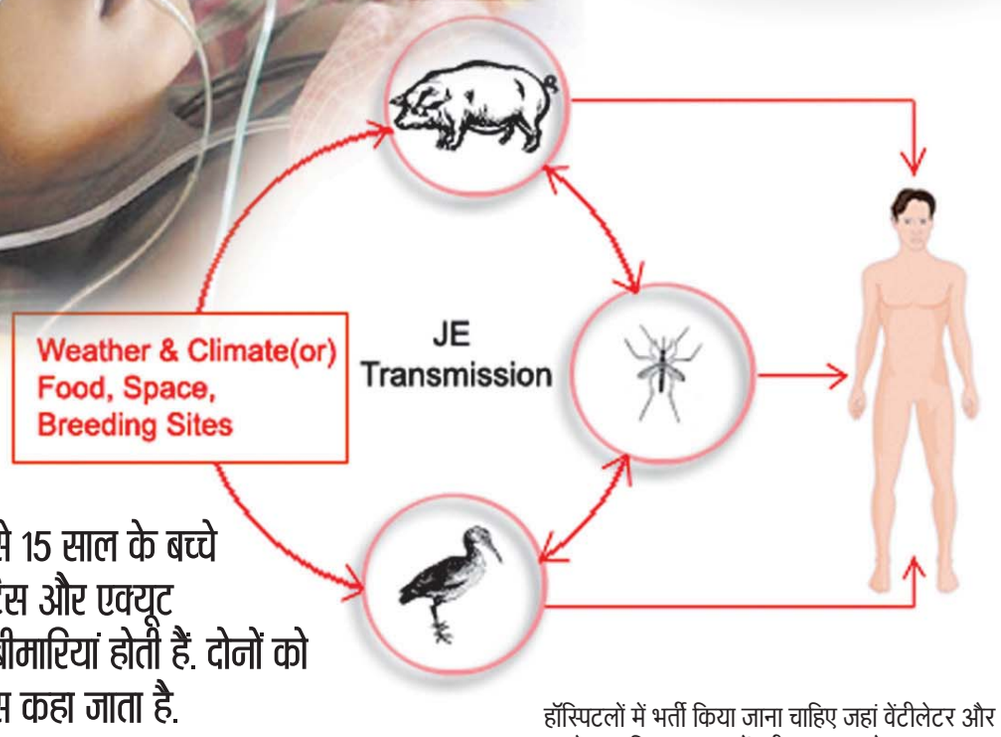

इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है. इससे सबसे अधिक शिकार तीन से 15 साल के बच्चे होते हैं. इसमें जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम नामक दो बीमारियां होती हैं. दोनों को ही सामान्य भाषा में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है.

सेफेलाइटिस के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चार दशक में इस बीमारी से बीस हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं. हर साल पांच-छह सौ बच्चे सरकारी रिकॉर्ड में मरते हैं जबकि हकीकत कुछ और ही है. वहीं इस बीमारी से लकवाग्रस्त हुए लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता. इंसेफेलाइटिस के सबसे अधिक शिकार तीन से 15 साल के बच्चे होते हैं. यह बीमारी जुलाई से दिसम्बर के बीच फैलती है. सितम्बर-अक्टूबर में बीमारी का कहर सबसे ज्यादा होता है. आंकड़े बताते हैं कि जितने लोग इंसेफेलाइटिस से ग्रसित होते हैं, उनमें से केवल 10 प्रतिशत में ही दिमागी बुखार के लक्षण जैसे झटके आना, बेहोशी और कोमा जैसी स्थिति दिखाई देती है. इनमें से 50 से 60 प्रतिशत मरीजों की मौत हो जाती है. बचे हुए मरीजों में से लगभग आधे लकवाग्रस्त हो जाते हैं और उनके आंख और कान ठीक से काम नहीं करते हैं. जिंदगीभर दौरे आते रहते हैं. मानसिक अपंगता हो जाती है.

बचाव घर को साफ-सुथरा रखें

मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें. रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें. इंसेफेलाइटिस रोग पैदा करने वाले मच्छर शाम को ही काटते हैं, इसलिए शाम को बाहर निकलते समय शरीर को ढककर ही निकलने को कहें. बच्चों को इंसेफेलाइटिस का टीका जरूर लगवाएं. इस टीके के तीन डोज होते हैं. यह शून्य से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाता है.

इलाज - इंसेफेलाइटिस के लिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, जिसे खाने के बाद मरीज ठीक हो जाएं. डॉक्टर लक्षणों को देखकर इलाज करते हैं. बीमारी की जितनी जल्दी जानकारी होती है, मरीज के बचने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है. इंसेफेलाइटिस में झटके, दिमाग में संक्रमण, डायरिया, ब्लड प्रेशर और न्यूमोनिया के लिए अलग-अलग दवाइयां दी जाती हैं . इंसेफेलाइटिस के मरीजों को अकसर वेंटीलेटर पर रखने की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में, मरीजों को उन्हीं हॉस्पिटलों में भर्ती किया जाना चाहिए जहां वेंटीलेटर और दूसरे आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हो अन्यथा जान जा सकती है.

कारण - इंसेफेलाइटिस फैलने के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब तक मुख्य कारणों में साफ-सफाई का अभाव माना जा रहा है. गंदगी की वजह से यह बीमारी एक-दूसरे में फैलती है. यह वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है लेकिन जो बीमारी यहां पाई जाती है वह वायरस से फैलती है. जो सूअर और हिरोनस नामक पानी की चिड़िया के शरीर पर पाये जाते हैं. अगर इन्हें काटने के बाद मच्छर किसी मनुष्य को काट लें तो उसे इंसेफेलाइटिस होने की पूरी आशंका होती है. दूषित पानी से भी इस बीमारी के वायरस लारवा के रूप में फलते-फूलते हैं.

लक्षण - शुरुआत के 15 दिनों तक आम फ्लू जैसे रहना. बुखार, सिर दर्द, उल्टी, डायरिया और जुकाम आदि की शिकायत. बाद में मरीज को झटके आना, बेहोशी छा जाना. मेमोरी लॉस और व्यावहारिक परिवर्तन होना. कुछ मरीजों को लकवा मार जाना.

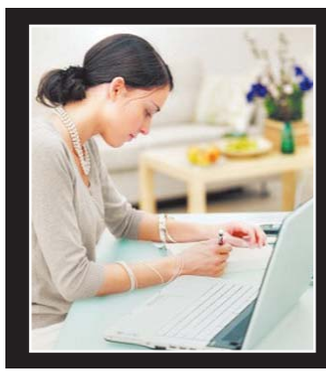

देर से सोना और कम सोना मोटापे को दावत

देर से सोने और कम नींद लेने वालों के लिए सावधान हो जाने की खबर है क्योंकि ऐसा करने से वे मोटापे का शिकार हो सकते हैं. अमेरिकी शोधकर्ताओं ने पाया कि देर से और कम सोने वाले युवा लोगों के मोटापे की चपेट में आने की आशंका बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वे देर रात के समय में कैलोरी का अधिक उपभोग करते हैं.एक अध्ययन में यह बात सामने आई है. पेन्सिलवेनिया विश्व विद्यालय में यह अध्ययन किया गया है. इसमें 225 स्वस्थ लोगों की शामिल किया गया जिनकी उम्र 22 से 50 साल के बीच थी. अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ चार घंटे की नींद लगातार पांच रातों तक लेने वालों का वजन उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बढ़ा जिन्होंने 10 घंटे की नींद ली. शोध में शामिल आंद्रिया स्पैथ का कहना है, ''पहले के अध्ययनों में भी यह कहा गया था कि कम सोने और वजन बढ़ने का संबंध होता है. परंतु हम इस अध्ययन में इससे हैरान रह गए कि कम सोने और देर से सोने वालों का वजन इतना अधिक बढ़ गया.''

सावधान!

खामोश हत्यारा है खर्राटा

नींद में खर्राटे आना, सोने पर सांस रुकना, दिन में ऊंघते रहना, थकान महसूस करना ये सभी लक्षण स्लीप एपनिया के हो सकते हैं. नींद में खर्राटे आना, सोने पर सांस रुकना या बेचैनी महसूस करना, दिन में अधिक नींद आना या लगातार ऊंघते रहना, दिन में थकान महसूस करना, सिरदर्द और सिर का भारी बने रहना, एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन, उदासीनता या अवसाद. ये सभी लक्षण स्लीप एपनिया के हो सकते हैं. हृदय रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि यह घातक बीमारी है. यह एक आम समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य से आम लोगों में इसके बारे में जानकारी का बहुत अभाव है. क्या है खर्राटा सोते समय शरीर की मांसपेशियों का लचीलापन अपेक्षाकृत बढ़ जाता है. यह प्रक्रिया श्वास-नली को खुला बनाए रखनेवाली मांसपेशियों में भी होती है. जब मांसपेशियों का यह लचीलापन एक स्तर से ज्यादा हो जाता है, तो श्वास-नली संकीर्ण हो जाती है. सांस लेने के दौरान खड़खड़ाहट की आवाज आने लगती है. यही आवाज खर्राटे के नाम से जानी जाती है. यह प्रक्रिया कुछ और बढ़ती है तो श्वास-नली पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है. इसके परिणामस्वरूप कई बार सांस रुक जाती है और शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है. यह रुकावट दस सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए भी हो सकती है. यह प्रक्रिया रात भर में सैकड़ों बार लगातार होती रहती है. इसके फलस्वरूप दिमाग, हृदय, गुर्दा, लीवर, पाचनतंत्र, जननतंत्र आदि अंग ऑक्सीजन की कमी से त्रस्त रहते हैं. ऑक्सीजन की कमी का सीधा परिणाम होता है कि नींद सुचारू रूप से पूरी नहीं हो पाती और दिन भर थकान, ऊंघ, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी आदि महसूस करते हैं. घबराएं नहीं, इलाज कराएं. यह बीमारी लाइलाज नहीं है. इसकी चिकित्सा सहज एवं सुगम है. इसके लिए जरूरी है कि अनुभवी चिकित्सक को समस्या से अवगत कराया जाए. इलाज के दौरान बताए चिकित्सकीय निर्देशों का सावधानी से पालन करें. छोटी सी मशीन सीपैप का उपयोग सोते समय करने से भी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है. इसके उपयोग से पहले अनुभवी चिकित्सक द्वारा जांच एवं उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

इन्हें भी आजमाएं - वजन नियंत्रित रखें, अधिक मोटापा भी हो सकता है.

बीमारी का कारण - देर रात तक टीवी नहीं देखें, सोने से एक या आध घंटा पहले ही टीवी बंद कर दें. देर रात तक चाय-कॉफी का सेवन न करें. सोने के लिए बिस्तर की साफ-सफाई जरूरी है, बिस्तर आरामदायक हो. अधिक मोटा तकिये का उपयोग न करें.

नीम की पत्तियां कैंसर में कारगर

कोलकाता के चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नीम की पत्तियों से प्रारम्भिक परीक्षण में सफलता पाई है. भारतीय डॉक्टरों का दावा है कि नीम से कैंसर का इलाज भी संभव है. चूहों पर प्रयोग के बाद उनका उत्साह और बढ़ा है. नीम के औषधीय गुण तो सदियों से जगजाहिर हैं हीं. अब तक इसकी पत्तियों का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में होने वाली छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के अलावा जीवाणुओं और कीटाणुओं से लड़ने में किया जाता है. अब कोलकाता स्थित चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (सीएनसीआई) के वैज्ञानिकों ने नीम को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ लड़ने का एक असरदार हथियार बनाने का प्रयास किया हैं. चूहों पर इसके सफल परीक्षण के बाद अब जल्दी ही मनुष्यों पर भी इसका परीक्षण किया जाएगा.

नीम में है नीम लीफ ग्लाइकोप्रोटीन

कोलकाता स्थित संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने लंबे अरसे तक चले परीक्षण के बाद छपे अपने दो पर्चो में बताया है कि नीम की पत्तियों से निकलने वाले एक खास किस्म के संशोधित प्रोटीन नीम लीफ ग्लाइकोप्रोटीन यानी (एनएलजीपी) के जरिए चूहों में ट्यूमर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने में कामयाबी मिली है. यह प्रोटीन कैंसर से सीधे लड़ने की बजाय ट्यूमर से निकलने वाले जहरीले व घातक रसायनों के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है. प्रतिरोधक कोशिकाओं कैंसर जैसी घातक बीमारियों से शरीर की रक्षा करती है. इस शोध टीम ने अध्ययन में पाया कि एनएलजीपी में ट्यूमर कोशिकाओं और ट्यूमर के विकास में सहायक गैर परिवर्तित कोशिकाओं से जुड़ी ट्यूमर की सूक्ष्म पारिस्थितिकी को सामान्य करने की शक्ति मौजूद है. मूल रूप से एनएलजीपी ट्यूमर की सूक्ष्म पारिस्थितिकी में ऐसे बदलाव लाता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है. वह कहते है कि कैंसर कोशिकाएं धीरे-धीरे विकसित होने पर प्रतिरोधक कोशिकाओं पर नियंत्रण कर लेती हैं. ऐसे में रोग से बचाने की जगह यह कोशिकाएं उल्टे कैंसर को फैलने में सहायता देने लगती हैं.

सुरक्षित साबित हुआ नीम का इलाज

शोध रिपोर्ट में इन वैज्ञानिकों ने सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित 17 मरीजों की कैंसर कोशिकाओं पर किए प्रयोग के नतीजे का भी खुलासा किया है. इस अध्ययन से उन्हें नीम की पत्तियों की सहायता से कैंसर के विकास पर अंकुश लगाने के तरीके का पता लगाया है. इससे पहले के कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में कहा गया था कि नीम प्रजनन तंत्र पर प्रतिकूल असर डाल सकता है. लेकिन हमने अपने शोध के जरिए इस संभावना को खारिज कर दिया है. इस शोध से अब तक के नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं. जानवरों पर किए गए परीक्षणों में यह यौगिक बेहद सुरक्षित साबित हुआ है. कोई 13 साल पहले जब इस टीम ने नीम की पत्तियों के कैंसर रोधक गुणों का पता लगाने की दिशा में पहल की थी तो सबसे पहले कुछ प्रयोग किए गए. प्रयोगशाला में तैयार की गई कैंसर कोशिकाओं के अध्ययन पर उनके विचारों को बल मिला. इस पर टीम के सदस्यों ने बर्दवान विश्वविद्यालय के केमेस्ट्री के प्रोफेसर के साथ मिल कर ग्लाइकोप्रोटीन की पहचान की. उनकी टीम अब इस प्रोटीन की और बारीकी से जांच करके पता लगाएगी कि इसका कौन सा तत्व सही मायने में सक्रिय है. इसकी वजह यह है कि इस प्रोटीन में तीन हिस्से हैं. टीम की कोशिश यह पता लगाने की है कि यह प्रोटीन रेजिस्टेंट कैंसर के मामलों में भी प्रभावशाली होगा या नहीं. वह कहते हैं, एक खास चरण के बाद कैंसर वाले ट्यूमर लाइलाज हो जाते हैं. उन पर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का भी कोई असर नहीं होता. उम्मीद है कि नीम लीफ ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे मामलों में कैंसर के इलाज को प्रभावशाली बना सकेगा. प्रतिरोधक कोशिकाओं में कैंसर को मारने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे सीडी-8 प्लस टी कोशिकाएं कहते हैं. ट्यूमर कोशिकाओं की वृद्धि के साथ ही एनएलजीपी की वजह से टी कोशिकाओं की तादाद भी बढ़ जाती है. इससे कैंसर को विकसित होने से रोकने में सहायता मिलती है. यही प्रोटीन टी कोशिकाओं को निष्क्रिय होने से भी बचाता है. परीक्षण की इस प्रक्रिया को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया समेत विभिन्न नियामक संस्थाओं के सामने पेश किया जाएगा. वहां से अनुमोदन मिलने के बाद मनुष्यों पर इसका परीक्षण शुरू किया जाएगा. वैज्ञानिकों के ताजा शोध के नतीजों से इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित लोगों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है.

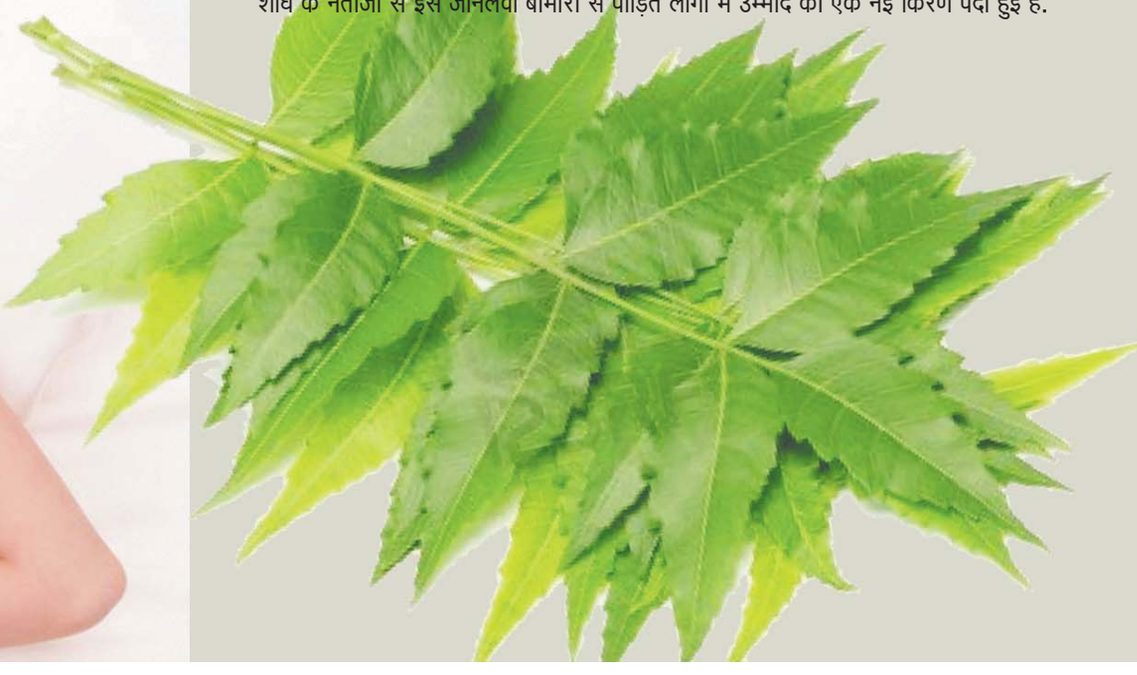

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

मास्क पहनने और सामाजिक दूरी सबंधी कोरोना दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर रष्ट चिंतित

नयी दिल्ली। सप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से बचाव के लिये सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर बृहस्पतिवार को गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के बारे मे सुझाव मांगे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता और दूसरे हितधारकों से कहा है कि वे मास्क पहनने की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के बारे में अपने सुझाव दें।

पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने यहां कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिये सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ को हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिये सुविधाओं की कमी के बारे में अवगत कराया गया था। इससे पहले, न्यायालय ने देश में, विशेषकर दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली में स्थिति बदतर हो गयी है जबकि गुजरात में यह नियंत्रण से बाहर हो रही है। न्यायालय कोविड-19 के मरीजो के उपचार और अस्पतालों में मृतकों के शव का कथित रूप से अनादर की घटनाओं का स्वत- संज्ञान लिये गये प्रकरण की सुनवाई कर रहा था।

योगी का निर्देश, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेजों में जाकर करें बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 महामारी के उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिये मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों में जाकर बैठक करने के निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कोविड-19 से बचाव तथा उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि सभी मेडिकल कॉलेजों में सम्बन्धित मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी जाकर बैठक करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि विशेषज्ञ चिकित्सक कोविड वार्ड में नियमित रू से 'राउण्ड' लें ताकि मरीजों को बेहतर उपचार सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के ज्यादा संक्रमण वाले जिलों लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, आगरा तथा वाराणसी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा आरएमएलआईएमएस जैसे चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक कर इन चिकित्सा संस्थानों की उपचार व्यवस्था की समीक्षा करें। योगी ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों में बेड की आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम करने में विफल रही केजरीवाल सरकार: कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम करने में नाकाम रही है। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की भी मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाना चाहिए।

पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतें बढ़ाना जनता के साथ विश्वासघात: अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बढोतरी को आम आदमी के साथ 'विश्वासघात' बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इन्हें कम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी करना आम आदमी के साथ 'विश्वासघात' है। गहलोत ने कहा, ''संप्रग सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल थीं लेकिन पेट्रोल, डीजल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर थे। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50 डॉलर प्रति बैरल से भी कम हो गई है लेकिन सरकार डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा ही रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल के दामों को स्थिर कर देती है लेकिन चुनाव खत्म होते ही पुनः दाम बढ़ा देती है। रसोई गैस के दाम में हालिया बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए गहलोत ने लिखा, ''कल रसोई गैस के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने आमजन का बजट बिगाड़ दिया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को खत्म कर दी है जिससे उज्ज्वला योजना में कनेक्शन पाने वाले गरीब लोग अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं।'' गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में जब सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिये थी, तब मोदी सरकार लोगों को महंगाई के बोझ तले दबा रही है।

पीएफआई के ठिकानों पर ईडी की मैराथन छापेमारी, सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े थे तार

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) के अध्यक्ष ओ एम अब्दुल सलाम और उसके केरल राज्य प्रमुख नसरुद्दीन एलामारोम के परिसरों समेत नौ राज्यों में पीएफआई के कम से कम 26 परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चेन्नई, तेनकासी और मदुरै (तमिलनाडु), बेंगलुरु, दरभंगा और पूर्णिया (बिहार), लखनऊ और बाराबंकी (उत्तर प्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), कोलकाता और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), जयपुर, दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र और केरल के कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम जिलों में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इन राज्यों के कम से कम 26 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस छापेमारी का मकसद पीएफआई और उससे संबंधित लोगों के खिलाफ धन शोधन के विभिन्न मामलों में जारी जांच के तहत सबूत एकत्र करना है। धन शोधन संबंधी विभिन्न मामलों को एक ही मामले में मिला दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि सलाम और पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव एलामारोम तथा संगठन के कई अन्य पदाधिकारियों के परिसरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी देश में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों, इस साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों और कई अन्य घटनाओं को भड़काने को लेकर ''वित्तीय संबंधों'' के आरोपों की पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही है।

इससे पहले, उसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ सहायक सलाम और दिल्ली में पीएफआई के कई अन्य पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज किए थे। सलाम और पीएफआई ने छापेमारी की इस कार्रवाई को ''हथकंडा'' बताया और आरोप लगाया कि किसानों के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत ये छापे मारे गए हैं। संगठन ने एक बयान में कहा, ''देशभर में पॉपुलर फ्रंट के राष्ट्रीय नेताओं के आवासों पर ईडी ने एक साथ छापे मारे। हमारा मानना है कि यह एजेंसी की ओर से की गई राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई है। इस प्रकार की छापेमारी हमारे देश में अकसर उस समय होती है, जब कभी सत्तारूढ़ सरकार किसी जन आंदोलन के कारण दबाव में होती है और वह देश का ध्यान भटकाना चाहती है।'' उसने कहा, ''मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और देश में असंतोष को दबाने के लिए हमेशा राष्ट्रीय एजेंसियों का इस हद तक इस्तेमाल किया है कि उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है।'' उसने कहा कि प्राधिकारी ''संगठन को संविधान विरोधी सीएए-एनआरसी के खिलाफ उसकी लड़ाई से रोकना चाहते है।'' पीएफए की स्थापना 2006 में केरल में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उसने कहा कि उसकी गतिविधियां ''पारदर्शी'' और सार्वजनिक हैं तथा उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।

एजेंसी ने पिछले महीने ट्वीट किया था, ''ईडी पीएफआई के पदाधिकारियों के पास से बरामद कुछ ठोस साक्ष्यों के आधार पर पीएफआई और भीम आर्मी के बीच वित्तीय जुड़ाव की जांच कर रहा है।'' भीम आर्मी ने 'पीटीआई भाषा' से कहा था कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। ईडी ने अगस्त में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को इस मामले में गिरफ्तार कर आरोप लगाया था कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों को भड़काने और फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों के लिए उन्हें धन मिला था। पीएमएलए के तहत 2018 से ही पीएफआई की जांच कर रही एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इन प्रदर्शनों और केरल स्थित संगठन के बीच ''वित्तीय जुड़ाव'' है। ईडी ने कहा था कि पिछले साल चार दिसंबर से इस साल छह जनवरी के बीच संगठन से जुड़े कई बैंक खातों में कम से कम 1.04 करोड़ रुपये जमा किए गए। सूत्रों ने कहा कि पीएफआई के बैंक खाते में जमा की गयी 120 करोड़ रुपये की रकम ईडी की जांच के घेरे में है। पीएफआई ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है।

भारत का उदय किसी के लिए खतरा नहीं, हम किसी से डरते भी नहीं: रक्षा सचिव

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

रक्षा सचिव अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के उदय से किसी को खतरा नहीं है और देश किसी से डरता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि देश के पड़ोस में स्थायित्व हो। कुमार ने कहा, ÷हमारे सामुद्रिक और राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है कि हमारे निकटस्थ पड़ोस में स्थायित्व बरकरार रहे और हिंद महासागर में ही नहीं बल्कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था स्थापित हो।'

मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की ओर से आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा, 'भारत का उदय किसी के लिए खतरा नहीं है और न ही हम किसी से डरते हैं।' कुमार ने कहा कि भारत के रक्षा संबंध मुक्त, खुली और नियम आधारित व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित हैं ताकि आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित हो जिससे भारत के एक सौ तीस करोड़ तथा क्षेत्र के दो सौ करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, 'हाल के वर्षों में हमने समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ सहयोग किया है और कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनसे सामंजस्य और संचालन को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में सम्पन्न हुआ मालाबार (सैन्य) अभ्यास, हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है।'

उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में मानव संसाधन पर खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। कुमार ने कहा, 'हम इसके लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहे हैं ताकि कम खर्च में काम हो सके, ऐसे तरीकों की तलाश कर रहे हैं जिससे खर्च कम हो सके और तकनीक का उपयोग किया जा सके।' उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में जहां अन्य मंत्रालयों के बजट में कटौती की गई वहीं रक्षा मंत्रालय का बजट प्रभावित नहीं होने दिया गया।

केंद्र सरकार को ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा- अगर नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो...

कोलकाता। (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि 'किसान विरोधी' नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सिलसेवार ट्वीट किये। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत चिंतित हूं। भारत सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेना चाहिए। यदि वह तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत से ही हम इन किसान विरोधी विधेयकों का विरोध कर रहे हैं।'

बनर्जी ने कहा, 'हमने शुक्रवार, चार दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है। केंद्र सरकार को इस जनविरोधी कानून को वापस लेना चाहिए।' उन्होंने कहा, ÷भारत सरकार हर चीज बेच रही है। आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, बीएसएनएल, बीएचईएल, बैंक, रक्षा इत्यादि को नहीं बेच सकते। गलत नीयत से लाई गई विनिवेश और निजीकरण की नीति वापस लीजिए। हम अपने राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनने देंगे।

दिल्ली की हवा में नहीं हुआ कोई सुधार, वायु गुणवत्ता अब भी 'बहुत खराब'

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार को 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही और आगामी दो दिन भी इसमें कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजे 342 रहा। बुधवार को शहर में 24 घंटे का औसत एक्यूआई 373 था। यह मंगलवार को 367, सोमवार को 318 और रविवार को 268 था। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 और 100 के बीच एक्यूआई 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच एक्यूआई 'सामान्य' 201 और 300 के बीच एक्यूआई 'खराब', 301 और 400 के बीच एक्यूआई 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार बृहस्पतिवार को हवा की दिशा मुख्य रूप से उत्तर की ओर रहेगी और अधिकतम छह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, इस मौसम में न्यूनतम तापमान अधिकतर दिनों में बादल नहीं होने के कारण सामान्य से दो से तीन डिग्री कम बना हुआ है। ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषक धरातल के निकट बने रहते हैं जबकि अनुकूल तेज हवाएं इन्हें छितरा कर अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। केंद्र सरकार की दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली ने बताया कि वायु गुणवत्ता के शनिवार तक 'बेहद खराब' श्रेणी में बने रहने की आशंका है। उसने पहले कहा था कि चार दिसंबर से सात दिसंबर के बीच इसके 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने का पूर्वानुमान है।

लव जिहाद के खिलाफ कर्नाटक में भी लागू होगा कानून : राज्य के गृह मंत्री

बेंगलुरु। (एजेंसी)।

कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा और अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए करते हैं, जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है। बोम्मई ने कहा, ''...जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस पर (कानून पर) विचार करना शुरू कर दिया है, तो हमने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि-इसे कैसे किया जाए, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दबाव या बलप्रयोग (धर्मांतरण में) का इस्तेमाल किया जाता है-यह मुख्य चीज है।'' उडुपी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी किया है और कर्नाटक के अधिकारियों को इसकी एक प्रति हासिल करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, ''अन्य राज्यों में उठाये गये कदमों के बारे में जुटाने के बाद कर्नाटक में भी हम निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है...।'' पिछले महीने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि सरकार प्रेम एवं विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख नलिन कुमार कतिल ने भी बुधवार को कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जाएगा।

बादल की पद्म पुरस्कार वापसी सरकार के मुंह पर तमाचा: मेधा पाटकर

इंदौर (मध्यप्रदेश)। नये कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाने को केंद्र सरकार के मुंह पर 'तमाचा' करार देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। किसानों और श्रमिकों के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाटकर की अगुवाई में शहर के रीगल चौराहे पर नये कृषि कानूनों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान पाटकर ने संवाददाताओं से कहा, हम उनके (बादल के) शुक्रगुजार हैं और उन्हें सलाम करते हैं। उनके पद्म पुरस्कार वापस करने से सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख ने कहा, हम अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियों से अपील करते हैं कि वे कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देते हुए सरकारी पुरस्कार लौटाएं और सरकार के मुंह पर तमाचा मारें। पाटकर ने आरोप लगाया कि नये कृषि कानूनों ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी की खुली छूट दे दी है जिससे देश की खाद्य सुरक्षा के सामने गहरा संकट खड़ा हो सकता है।

मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

मुंबई। (एजेंसी)।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। अदालत ने सभी सात आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी आर सितरे ने इससे पहले भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, ठाकुर और तीन अन्य आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। न्यायाधीश के सामने केवल तीन आरोपी प्रस्तुत हुए। अन्य तीन आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि कोविड-19 की स्थिति के चलते उनके मुवक्किल पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को पुनः शुरू होगी। महाराष्ट्र में मुंबई से 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखी विस्फोटक सामग्री में धमाका हो गया था जिससे छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस बीच बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक खंड पीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। याचिका में कहा गया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया जाए। अदालत ने पुरोहित के वकील के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर तय की है।

भोपाल गैस त्रासदी की 36 वीं बरसी पर मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन

भोपाल। (एजेंसी)।

भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे की 36 वीं बरसी के उपलक्ष्य में आज गैस पीड़ितों के चार संगठनों ने पीड़ितों की बिगड़ती स्वास्थ्य और स्थानीय मिट्टी और भूजल में जारी प्रदूषण के लिए अमरीका की डाव केमिकल कम्पनी का कानूनी ज़िम्मेदारी से भागने की तीव्र भत्सना की है। संगठनों ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर अपराधी कम्पनी से सही मुआवज़ा हासिल नहीं करने और पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले इन संगठनों ने यूनियन कार्बाइड कारखाने पास मानव श्रृंखला बनाकर और डाव कैमिकल का पुतला जलागकर अपना रोश प्रगट किया।

इस दौरान भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा कि 'सन 2005 में डाव केमिकल का भारत के बाज़ार में मात्र 2.5/ हिस्सा था, जबकि 2015 से इस कम्पनी का भारतीय बाज़ार में हिस्सा बढ़ता जा रहा है और फिलहाल यह आँकड़ा 22/ तक पहुँच गया है। यह तय है की इस विदेशी कम्पनी का हमारे प्रधानमन्त्री के साथ करीबी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। इस बीच पिछले दिसम्बर से गैसकाण्ड की वजह से विधवा हुई पाँच हज़ार महिलाओं की एक हज़ार रूपए की मासिक पेन्शन प्रदेश सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है ।'

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से मारे गए गैस पीड़ितों के झूठे आँकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एन्ड एक्शन की रचना धींगरा ने कहा, 'हम सरकारी अधिकारियों को चुनौती देते हैं की वे ऐसा एक सबूत पेश करें कि पिछले 36 सालों में हमने कभी तथ्यात्मक और वैज्ञानिक आधार के बगैर कोई बात कही हो। यह वही पुराना सरकारी छल है, हादसे की वजह से हुई मौतों और पीड़ितों को हुई बीमारियों के बारे में सरकारी अधिकारी गैस काण्ड की सुबह से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। मौतों का सरकारी आँकड़ा वास्तविक आँकड़े से पाँच गुना कम है और 90/ से अधिक गैस पीड़ितों के बारे में यह बताया जा रहा है की उन्हें सिर्फ एक बार अस्पताल जाना पड़ा।'

वही भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा,÷पिछले दस सालों में केंद्र तथा प्रदेश सरकारों के अधिकारियों ने हमें सर्वोच्च न्यायालय में अमरीकी कम्पनियों से अतिरिक्त मुआवज़ा के लिए लंबित सुधार याचिका में मौतों और बीमारियों के आँकड़े सुधारने का लिखित आश्वासन दिया है। पर इन आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ गैसकाण्ड के दूरगामी प्रभाव पर सरकारी चिकित्सीय शोध या तो बंद कर दिया गया है या दबा दिया गया है। गैसजनित पुरानी बीमारियों का इलाज आज भी लाक्षणिक दवाओं से हो रहा है, पीड़ितों के पुनर्वास का काम बंद पड़ा है और मिट्टी और भूजल की ज़हर सफाई के लिए कोई सरकारी योजना तक नहीं है।

जबकि डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे संगठन की नौशीन खान ने कहा कि 'भोपाल के गैस पीड़ितों और दुनिया भर में औद्योगिक प्रदूषण से बीमार लोगों पर कोरोना महामारी के भयावह असर ने रसायन कम्पनियों पर कानूनी शिकंजा कसने की ज़रुरत को बड़े शिद्दत से रेखांकित किया है। पिछले 36 सालों में भारत और अमरीका की न्याय व्यवस्था यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से क़ानून का पालन करवाने में नाकाम साबित हुई है। भोपाल में जारी अन्याय और बदहाली से कम्पनियों को मानवता और पर्यावरण के खिलाफ अपराध जारी रखने का प्रोत्साहन मिल रहा है।'

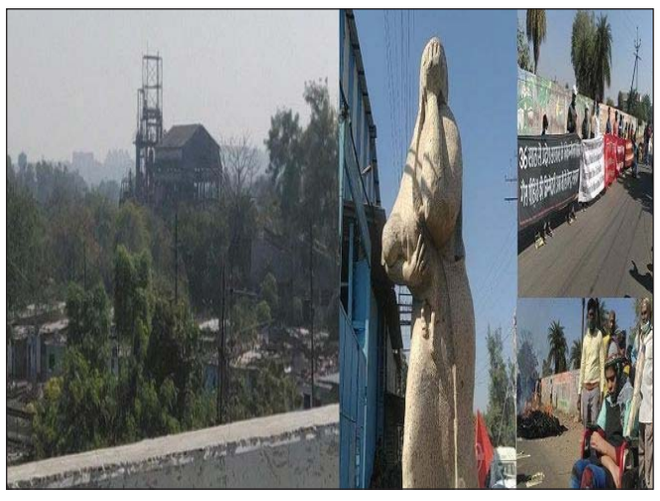

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)